Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-14 16-31 जुलाई, 2022 (पाक्षिक) ₹20

'तेलंगाना का भाजपा में विश्वास बढ़ रहा है'

'तुष्टीकरण' नहीं 'तृप्तीकरण' से होगा 'सबका विकास'

अगला दशक भारत का दशक है

गत आठ वर्षों में अविश्वसनीय उपलब्धियां, व्यापक परिवर्तन

गुजरात दंगा: सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका, प्रधानमंत्री मोदी को क्लीनचिट

हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत करते भाजपा कार्यकर्तागण

हैदराबाद (तेलंगाना) में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

सिकंदराबाद परेड ग्राउंड (तेलंगाना) में आयोजित विजय संकल्प सभा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेतागण

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर पौधारोपण करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

गुरुग्राम (हरियाणा) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुनते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और संगठन को मजबूत बनाना है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी की द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 2 एवं 3 जुलाई, 2022 को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश...

10 अगला दशक भारत का दशक है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के पिछले आठ वर्षों में...

15 गत आठ वर्षों में अविश्वसनीय उपलब्धियां, व्यापक परिवर्तन

आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत की...

21 आज का भारत तुष्टीकरण के कालखंड से आगे बढ़कर तृप्तीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 जुलाई, 2022 को हैदराबाद (तेलंगाना)...

30 तेलंगाना का भाजपा में विश्वास बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सपन्न होने के बाद 3 जुलाई, 2022 को हैदराबाद...

साक्षात्कार

जिन लोगों ने आरोप लगाए, वे मोदीजी से माफी मांगें / **अमित शाह** 31

श्रद्धांजलि

हिमाचल भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश शर्मा नहीं रहे 23

प्रधानमंत्री का ब्लॉग

मेरे मित्र शिंजो आबे... / **नरेन्द्र मोदी** 28

अन्य

तेलंगाना पर प्रेस वक्तव्य 24

कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को दी मंजूरी 32

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना हुई चालू 32

जून, 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह साल-दर-साल 56% बढ़कर 1,44,616 करोड़ रुपये हुआ 33

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर अब तक का सर्वाधिक 57,586.48 करोड़ रुपये रहा 33

'डॉ. मुकर्जी एक महान राष्ट्रभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा और महान शिक्षाविद् थे' 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमारे लिए विकास का अर्थ है— गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माताएं-बहनें, सबका सशक्तीकरण।

जगत प्रकाश नड्डा

सशक्त गांव के बिना सशक्त भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए, आज सूचना तकनीकी के इस्तेमाल से सशक्त गांव का निर्माण हो रहा है। 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के परिकल्पक और सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस दूरदर्शिता के लिए बधाई के पात्र हैं।

अमित शाह

दुनिया ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों मॉडल को अपनाया, लेकिन ये दोनों ही extreme मॉडल हैं। सहकारी मॉडल मध्यम मार्ग है और यह भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। और मोदी सरकार इस सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी सहकारी मॉडल से भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने का काम कर रही है।

राजनाथ सिंह

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन उन सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है जिन्होंने हमें, हमारे देश और समाज को दिशा और प्रेरणा दी है। देश में ज्ञान की गंगा अविरल बहती रहे और भारत धनवान और ज्ञानवान बने, यही ईश्वर से कामना है।

बी.एल. संतोष

तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में कुछ दलों और विचारधाराओं द्वारा चलायी जा रही असहिष्णु राजनीति का सामना भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता पूर्ण गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कर रहा है।

नितिन गडकरी

'मन की बात' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनेकविध विषयों पर बात की और अनेक प्रेरक विचार साझा किए। जून, 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा भारतीयों पर थोपे गए आपातकाल का उन्होंने जिक्र किया। इस तानाशाही आपातकाल के देश भर में हुए परिणामों की उन्होंने याद दिलाई।

संपादकीय

'सत्यमेव जयते'

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात दंगों पर गठित एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने से देश की जनता का विश्वास भारतीय न्याय व्यवस्था पर और भी अधिक गहरा हुआ है। जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक और अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक स्वर में एसआईटी की 'क्लोजर रिपोर्ट' को सही ठहराया है। ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायलय ने न केवल इस 'क्लोजर रिपोर्ट' को सही ठहराया है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र की भी कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। कुछ 'कुंठित अधिकारी', एनजीओ, मीडिया एवं विदेशी मीडिया का एक वर्ग तथा कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों द्वारा रचित षड्यंत्र का अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि षड्यंत्रकारियों के गठजोड़ ने निरंतर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर राष्ट्र को दिग्भ्रमित तथा जांच एजेंसियों की आंखों पर धूल झोंकने के कुप्रयास किये। वर्षों तक इस मामले को किसी न किसी बहाने से खींचते रहने का षड्यंत्र अब अंततः सर्वोच्च न्यायालय में ध्वस्त हो चुका है। सत्य की जीत हुई और षड्यंत्रकारी देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब देश के कानून के अंतर्गत इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन्हें कठोर से कठोर दंड मिले।

> **लंबी अग्निपरीक्षा के दौरान पूरा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा रहा, श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं सब कुछ सहते हुए धैर्य एवं सहनशीलता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया**

एक ओर जहां इस लंबी अग्निपरीक्षा के दौरान पूरा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं सब कुछ सहते हुए धैर्य एवं सहनशीलता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह उनके न्यायालय, न्याय प्रक्रिया एवं न्यायिक व्यवस्था पर अटूट विश्वास के कारण संभव हो पाया। गोधरा एवं गुजरात दंगों की आड़ में झूठ, फरेब तथा तथ्यों को विकृत कर गुजरात एवं प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था। यह राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त मानसिकता से उपजा हुआ षड्यंत्र था जो बार-बार जनता के न्यायालय में हारने के कारण राजनीतिक बदले की भावना से ग्रस्त था। बरसों तक यह षड्यंत्र अलग-अलग रूपों में, विभिन्न मंचों पर और यहां तक की विदेश में भी अपना फन फैलाता रहा, परंतु हर जगह सत्य की विजय हुई। इस बरसों तक चलने वाली अग्निपरीक्षा का सामना असाधारण धैर्य, अत्यंत मर्यादित भाव, अदम्य साहस एवं अपराजेय आत्मबल के साथ-साथ लोकतंत्र पर अडिग विश्वास एवं जन-जन के समर्थन एवं स्नेह के बल पर ही संभव था। आज पूरे राष्ट्र को श्री नरेन्द्र मोदी पर एक बार पुनः गौरव का अनुभव हो रहा है।

एक ओर जहां श्री नरेन्द्र मोदी ने इस पूरे षड्यंत्र काल में भारतीय संविधान, देश के कानून, लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय व्यवस्था के प्रति अपनी आदर एवं श्रद्धा का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र के इन गौरवशाली स्तंभों का कांग्रेस निरंतर अपमान करती रहती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष एवं एक पूर्व अध्यक्ष को जांच के लिए बुलाया जाता है, तब कांग्रेस सड़कों पर तमाशा करने से बाज नहीं आती। इतना ही नहीं, कांग्रेस एवं उसके नेता न्यायालय, चुनाव आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी के साथ हमला कर उन पर दबाव बनाने की राजनीति करती रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के द्वारा बार-बार चुनावों में नकारे जाने के बाद भी कांग्रेस, भारत को अपनी जागीर समझती है। यह लोग वंशवादी राजनीति में इतने भ्रमित हो चुके हैं कि अपने 'प्रथम परिवार' को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। लोकतांत्रिक भावना से भरे लोग आज पूरी तरह से कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के विरोध में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने षड्यंत्रकारियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है तथा कांग्रेस एवं इस षड्यंत्र में लिप्त दोषी अब कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और संगठन को मजबूत बनाना है: जगत प्रकाश नड्डा

अध्यक्षीय उद्बोधन

भारतीय जनता पार्टी की द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 2 एवं 3 जुलाई, 2022 को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का शुभारंभ किया। मंच पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के पूरे सत्र के दौरान सदस्यों को प्रधानमंत्रीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्रीजी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक स्थल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरा हैदराबाद शहर भगवामय हो गया। भारत माता की जय और 'मोदी-मोदी' के नारे से पूरा कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो रहा था।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति ख़त्म हुई है और विकासवाद, राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। श्री नड्डा ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि जहां एक ओर भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, वहीं विपक्ष का व्यवहार अत्यंत ही गैर-जिम्मेदाराना रहा है। विपक्ष तर्कविहीन थोथी राजनीति कर देश की जनता को गुमराह कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी सफलता में नए आयाम स्थापित किये हैं। उन्होंने संगठन को और मजबूत करने पर बल देते हुए कहा कि जिन-जिन राज्यों में हम अब तक सफल नहीं हो पाए, हमें वहां काम करना है और जनता का आशीर्वाद हासिल करना है। हर बूथ पर संगठन को मजबूत करना है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदुः

- आजादी का अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों से भरे हुए 8 सफल वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के तौर पर 20 वर्ष पूरे किये हैं जो कि एक महान उपलब्धि है। मैं इस मंच से प्रधानमंत्रीजी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
- देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले आजादी के सभी नाम-अनाम सिपाहियों से देश की वर्तमान पीढ़ी का परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं इस मंच से आजादी के गुमनाम सिपाहियों को नमन करता हूं।
- जिस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हमारे मनीषी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जीजी ने जनसंघ की स्थापना की थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकता, आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की कुशल रणनीति के बल पर वह सपना भी साकार हुआ और जम्मू-कश्मीर से सदा-सदा के लिए धारा 370 धाराशायी हुई।
- एकात्म मानववाद और अंत्योदय हमारी पार्टी की मूल अवधारणा रही है। आज 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत को सरकार का मूल मंत्र बनाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जन-जन के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।
- आजादी के बाद से लेकर अब तक आदिवासियों के सर्वसमावेशी कल्याण के लिए यदि किसी ने सबसे अधिक काम किया तो वे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्रीजी ने अहर्निश कार्य किया है। हमारी पार्टी ने इस बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आज इस मंच से देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर आदरणीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी का समर्थन करें।
- कल ही जनता दल (सेक्युलर) और शिरोमणि अकाली दल ने माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री सुखबीर बादल को धन्यवाद देता हूं। मैं अन्य सभी दलों से भी अपील करता हूं कि वे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी सफलता में नए आयाम स्थापित किये हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधान सभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक सफलता अर्जित की। उत्तर प्रदेश (एनडीए) और उत्तराखंड में भाजपा को रिकॉर्ड दूसरी बार दो-तिहाई बहुमत मिला। मणिपुर में भाजपा को पहली बार अपने दम पर बहुमत मिला और लगातार दूसरी बार हमारी सरकार बनी। एक तटीय प्रदेश, एक उत्तर-पूर्व का राज्य, एक पहाड़ी राज्य और एक देश का सबसे बड़ा प्रदेश – हर क्षेत्र की जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास और प्रगाढ़ हुआ है।
- उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी। साथ ही, दूसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी से हमारा वोट भी लगभग 9 प्रतिशत अधिक रहा। यूपी के 23 जिलों में हमने क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 399 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसमें से 387 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 377 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

> **एकात्म मानववाद और अंत्योदय हमारी पार्टी की मूल अवधारणा रही है। आज 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत को सरकार का मूल मंत्र बनाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जन-जन के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं**

- उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिलीं। आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 68 सीटों पर उसके उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। गोवा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी। यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 35 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने भी गोवा विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर 21 सीटों पर उसकी जमानत भी जब्त हुई।
- विधानसभा चुनावों के साथ-साथ देश में हुए लगभग सभी स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देश में हुए लगभग सभी निकाय चुनावों में भाजपा को शानदार जीत मिली है। गुजरात और असम में हम शत-प्रतिशत चुनाव जीते। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में भी भाजपा ने स्थानीय निकाय

चुनावों में शानदार जीत दर्ज की।

- हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में हमने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीट सपा से छीन ली है। त्रिपुरा में चार विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव में तीन पर भाजपा विजयी हुई है।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति ख़त्म हुई है और विकासवाद, राजनीति का केंद्रबिंदु बना है। उनके नेतृत्व में देश की राजनैतिक कार्य-संस्कृति भी बदली है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार प्रो-एक्टिव, प्रो-रिस्पोंसिव और प्रो-पुअर सरकार है जो जनसेवा के लिए सतत कटिबद्ध रहती है। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने देश के लोकतंत्र में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस और विकासवाद के सिद्धांत को स्थापित किया है।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सौभाग्य योजना, जल-जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जन-धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व वंदन योजना जैसे इनिशिएटिव ने भारत में कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक पिछले दो वर्षों से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार इस पर लगभग तीन लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना— इन तीन योजनाओं में लगभग 40 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच दिया गया है।

- आज भारत डिजिटल क्रांति को नया आयाम दे रहा है। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजेक्शन का 40 प्रतिशत हिस्सा भारत से आता है। देश में इंटरनेट कनेक्शन में लगभग 231 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अब तक लगभग 133 करोड़ आधार कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

- कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। पूरी दुनिया आज भी कोरोना के विपरीत प्रभाव से उबरने के लिए संघर्षरत है, लेकिन भारत ने इस दौरान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 8.4 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि दुनिया की औसत आर्थिक विकास दर महज 6 प्रतिशत के आसपास है। विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व के बल पर भारत में गरीबी 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत के नीचे चली आई है। अत्यधिक गरीबी की दर भी कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के बावजूद 1 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

- वैश्विक कोरोना महामारी के बाद भी भारत की विकास दर 2021-22 में 8.4 प्रतिशत रही है जो विश्व में सर्वाधिक है। कोविड की परेशानियों के बावजूद जीएसटी संग्रह डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। रिटेल ग्रोथ में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। भारी मात्रा में एफडीआई भारत आया है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात भी किया है। 100 लाख करोड़ रुपये की पीएम गतिशक्ति योजना बुनियादी ढांचे की लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा और लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा। बड़े पैमाने पर क्रियान्वयित की गई इस परियोजना से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में वैक्सीन का निर्माण हुआ है और अब तक लगभग 197 करोड़ वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किये जा चुके हैं। हमने 1.48 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज मुफ्त में देशों को दी है। लगभग 100 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराये हैं। हमारी वैक्सीन सस्ती और टिकाऊ है। हमारे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की पूरी दुनिया में सराहना हुई है।

वैश्विक कोरोना महामारी के बाद भी भारत की विकास दर 2021-22 में 8.4 प्रतिशत रही है जो विश्व में सर्वाधिक है। कोविड की परेशानियों के बावजूद जीएसटी संग्रह डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। रिटेल ग्रोथ में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति— दोनों पर काम हुआ। इसके लिए हजारों-लाखों सुझावों पर अध्ययन-मनन हुआ और मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्टीय स्वास्थ्य नीति— दोनों ही नीतियां भारत की मिट्टी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं जो भारत की जमीन और जड़ों से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का भी ध्यान रखा गया है और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये गए हैं।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं तो सुरक्षित हुई ही हैं, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। कांग्रेस की सरकार में तो एक रक्षा मंत्री बोलते थे कि हम सीमा पर सड़क बनाएंगे तो पड़ोसी देश नाराज हो जाएगा। आज प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में सही मायनों में स्वतंत्र विदेश नीति का सूत्रपात हुआ है।

- एक समय दुनिया में हमारी छवि एक पिछलग्गू, पिछड़े और भ्रष्ट देश की थी, जबकि आज पूरे विश्व में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। हाल ही में संपन्न G-7 देशों की बैठक में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यह विश्व पटल में भारत की बढ़ती साख और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का भारत को देखने के नजरिये में बदलाव की कहानी को रेखांकित करता है। विदेशों में रह रहे Indian Diaspora को प्रधानमंत्रीजी के बहुआयामी नेतृत्व के कारण एक आवाज मिली है। ये प्रधानमंत्रीजी की ही विदेश नीति का परिणाम है कि हम युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने 23,000 छात्रों को सकुशल देश वापस लेकर आ सके।

- जहां एक ओर भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, वहीं विपक्ष का व्यवहार अत्यंत ही गैर-जिम्मेदाराना रहा है। विपक्ष तर्कविहीन थोथी राजनीति कर देश की जनता को गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों पर जनता को गुमराह किया।

- विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने लद्दाख और डोकलाम पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने राफेल पर जनता को गुमराह किया। देशहित के लिए जरूरी सुधारों को अटकाना, लटकाना और भटकाना— यही विपक्ष का उद्देश्य रह गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते-करते विपक्ष अब देश के विरोध पर उतारू हो गया है।

विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने लद्दाख और डोकलाम पर जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने राफेल पर जनता को गुमराह किया। देशहित के लिए जरूरी सुधारों को अटकाना, लटकाना और भटकाना - यही विपक्ष का उद्देश्य रह गया है

- भाजपाशासित राज्यों में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के आधार पर विकास की राजनीति हो रही है, विपक्ष शाषित राज्य में तुष्टीकरण की घोर पराकाष्ठा की राजनीति हो रही है।

- भाजपाशासित राज्यों में इस बात की प्रतिस्पर्द्धा है कि गरीबों के सबसे अधिक मकान किसने बनाए हैं, ग्राम विकास में कौन सबसे आगे है, सड़कें किसने अधिक बनाई है, गरीबों तक राशन किसने अधिक पहुंचाया है, मेडिकल कॉलेज किसने अधिक खोले हैं, सबसे अधिक वैक्सीन किसने लगाई है, सबसे अधिक शौचालय किसने बनाए हैं। जबकि, विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में कौन आगे है, गरीबों का राशन लूटने में कौन सबसे अधिक आगे है, भ्रष्टाचार में कौन सबसे आगे है और परिवारवाद की राजनीति में कौन सबसे आगे है।

- कोविड के संक्रमण काल में जब सभी राजनीतिक दल लॉकडाउन की अवस्था में चले गए, क्वारंटाइन हो गए थे तब प्रधानमंत्रीजी के सेवा ही संगठन मंत्र के आह्वान पर पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने आप को मानवता की सेवा में झोंक दिया। यह हमारे सामाजिक आयाम को रेखांकित करता है।

- पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू-कश्मीर में काफी कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं इन प्रदेशों में कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए समर्पित भाव से कार्य करने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं।

- जिन-जिन राज्यों में हम अब तक सफल नहीं हो पाए, हमें वहां काम करना है और जनता का आशीर्वाद हासिल करना है। हर बूथ पर संगठन को मजबूत करना है। जिन राज्यों में हम सरकार में हैं, वहां भी जिन-जिन बूथों पर हम कमजोर हैं, वहां जमकर मेहनत करनी है। हमने ऐसे लगभग 50,000 बूथों को चिह्नित किया है जहां हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और संगठन को मजबूत बनाना है।

- उत्तर-पूर्व के राज्य भीषण बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं। मणिपुर में भू-स्खलन के कारण काफी नुकसान हुआ है। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में त्वरित सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है। हमारी सरकारें भी लगातार राहत अभियान चला रही हैं। सरकार और संगठन मिलकर इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं।

- भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में अब हम भाजपा को वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 'भाजपा को जानें (Know BJP)' अभियान शुरू किया है। अब तक मैं 40 से अधिक देशों के 'राजनयिकों (Head of Mission)' के साथ संवाद कर चुका हूं। नेपाल के प्रधानमंत्रीजी, सिंगापुर के विदेश मंत्री और वियतनाम की सत्तारूढ़ पार्टी के तीसरे शीर्ष नेता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय आये और उन्होंने वहां काफी समय बिताते हुए भाजपा की कार्यसंस्कृति को समझा, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दुनिया के बदलते दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। ■

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

अगला दशक भारत का दशक है

आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 02-03 जुलाई, 2022 को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 'आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प' प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत की विकास गाथा प्रधानमंत्री मोदीजी की आत्मनिर्भरता और गरीब कल्याण के संकल्प एवं सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। आगे कहा गया है कि जहां सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विकास पथ पर वापस आने के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत, महामारी के अपने कुशल प्रबंधन, सुविचारित नीतिगत प्रतिक्रिया, प्रो-एक्टिव, प्रो-रेस्पोंसिव और प्रो-पुअर नीति और इसके त्वरित क्रियान्वयन के कारण, इससे उबर कर प्रगति व विकास की नई कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ा है। हम यहां 'आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प' प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के पिछले आठ वर्षों में भारत 'सबका साथ और सबका विकास' के प्रमुख सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका है और भारत की विकास गाथा प्रधानमंत्री मोदीजी की आत्मनिर्भरता और गरीब कल्याण के संकल्प एवं सर्वस्पर्शी व सर्व-समावेशी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। इसी लय से राष्ट्र की यह विकास गाथा और गतिमान होती रहेगी। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के सत्ता संभालने के बाद वास्तव में भारत का चहुंमुखी विकास हुआ है। आठ वर्षों में देश की इतनी प्रगति प्रधानमंत्री मोदीजी की सोच का परिणाम है। हमें 2014 के चुनाव में प्रचंड जीत के कुछ ही घंटों बाद मोदीजी द्वारा दिया गया वह विजय-भाषण आज भी स्मरण है। उसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि भारत का समावेशी विकास करना है। उन्हें पता था कि इसके लिए उन्हें डिलीवरी तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। कांग्रेस के शासन में योजनाएं और नीतियां कागजों में सिमट कर रह जाती थीं। डिलीवरी तंत्र में छेद ही छेद थे। हर जगह लूटखसोट थी। किंतु मोदीजी की सरकार आई और योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया। मोदीजी के डिलिवरी तंत्र में सुनिश्चित किया गया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदीजी का 'सबका साथ-सबका विकास' मंत्र था। कांग्रेस शासन के समय सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ चेहरा और पहचान देखकर दिया जाता था, कांग्रेस के शासन में योजनाएं वोट बैंक की राजनीति करते हुए कुछ विशेष समूहों या जातियों के लिए ही बनाई जाती थीं। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने यह पक्षपाती व्यवस्था बदली और सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हों और इनका लाभ निष्पक्षता से सभी वर्गों, समुदायों और व्यक्तियों को मिले।

प्रधानमंत्री मोदीजी की सोच से जो एक और नया प्रतिमान आया, वह यह था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश में यह विश्वास भरा कि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास श्रमशक्ति है, हमारे पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं। हम सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाएंगे, 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी करेंगे, और अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में ले जाने के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदीजी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना 'वसुधैव कुटुंबकम' पर आधारित है— जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है तो यह स्व-केंद्रित प्रणाली का पक्ष नहीं लेता है। भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में समस्त विश्व के सुख, सहयोग और शांति का भाव निहित है।

प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए पांच क्षेत्र चुने गए हैं:

- **अर्थव्यवस्था:** ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि क्रमिक परिवर्तन के बजाय एक साथ बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हो।
- **मूलभूत अवसंरचना:** ऐसी मूलभूत अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान और विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला हो।
- **तंत्र:** ऐसा तंत्र हो जो आधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने वाला हो और समाज में डिजिटल तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने वाला हो।
- **जनांकिकी:** अपनी बहुमुखी प्रतिभावान और युवा जनांकिकी का सर्वोत्तम उपयोग हो।
- **मांग:** हमारे पास बड़े स्तर पर घरेलू बाजार और मांग वाले क्षेत्र हैं, जिनका पूरी क्षमता से दोहन हो।

कोविड राहत और पुनरुत्थान

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के दूसरी बार पदभार संभालने के तुरंत बाद विश्व के साथ-साथ भारत को भी एक वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। यद्यपि, भारत न केवल अपने लोगों की रक्षा करने और मानवता की सहायता के लिए लगभग 100 देशों तक सहायता का हाथ बढ़ाने में सफल रहा, अपितु प्रत्येक स्तर पर और शक्तिशाली होकर उभरा। कुशल प्रशासन, नवोन्मेषी सोच, अच्छी तरह से जांची-परखी नीतियां, जन-कल्याण की नीतियों का त्वरित क्रियान्यवन और 1.35 अरब लोगों की सेवा करने की अटूट प्रतिबद्धता ने इस सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया।

> **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने न केवल कोवैक्सिन नामक अपनी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लगभग तुरंत ही विकसित कर ली, अपितु विदेशों में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का स्वदेश में साझेदारी के आधार पर उत्पादन भी किया**

रिकार्ड समय में भारत की स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलता की उल्लेखनीय गाथा है। भारत ने डेढ़ वर्ष में अपने नागरिकों को 191 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी है। ध्यान रहे, यह वही भारत है जिसे विदेशों में खोज हो जाने के पश्चात भी पोलियो वैक्सीन के लिए 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने न केवल कोवैक्सिन नामक अपनी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लगभग तुरंत ही विकसित कर ली, अपितु विदेशों में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का स्वदेश में साझेदारी के आधार पर उत्पादन भी किया। सरकार के सूक्त वाक्य 'वसुधैव कुटुंबकम' पर आगे बढ़ते भारत ने लगभग 100 देशों को इन टीकों का निर्यात किया। महामारी के समय मृत्यु दर और रुग्णता दोनों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य का मूलभूत ढांचा महत्वपूर्ण था। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश भर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की

मूलभूत अवसंरचना को तेजी से हजारों गुना बढ़ाया है। उदाहरण के लिए देश में गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) में पेशेंट बेड्स की संख्या मार्च 2020 में 2,168 थी, जिसे जनवरी, 2022 तक बढ़ाकर 1.39 लाख कर दिया गया। इसी अवधि में देशभर में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (पीएसए) प्लांट्स (ऑक्सीजन प्लांट्स) और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट की निर्माण क्षमता भी इसी परिमाण में बढ़ाया गया। यह देश के स्वास्थ्य ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन और सशक्त रूपांतरण को दर्शाता है।

आर्थिक पुनरुद्धार- पहल, वृहद-दृष्टिकोण और लक्षण

कोविड-19 ने न केवल भारत, अपितु विश्व के लगभग सभी देशों की आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया। संक्रमण के भय ने श्रम-बल की भागीदारी के साथ-साथ श्रमिकों को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं की इच्छा को भी प्रभावित किया। अनेक प्रकरणों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारों द्वारा लॉकडाउन लगाए गए, जिसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। एक दूसरे से जुड़े विश्व में, जहां कहीं भी उत्पादन में व्यवधान आया, वहां इससे आपूर्ति-शृंखला टूटी और इसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। ऐसे वातावरण में भारत में स्थिर कीमतों पर 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में -6.6 प्रतिशत हो गई थी, किंतु भारत महामारी के कुशल प्रबंधन के साथ ही 2021-22 में अनुमानित 8.7 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने में सफल रहा। आवासन क्षेत्र में बाजार के उभरने के प्रत्यक्ष संकेत दिख रहे हैं।

महामारी और यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद से ही हमारी सरकार ने असाधारण उपाय किए हैं। हमने अपने महान देश के आमजन और महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं आरंभ की हैं और कदम उठाए हैं। हमने छोटे व्यापार को ऊपर उठाने के लिए अनेक उपाय किए हैं और इसके लिए बड़े परिमाण में धन की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदीजी ने अनेक दीर्घावधि योजनाएं आरंभ कर इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने का कदम उठाया है। हम अपने प्रधानमंत्रीजी को नमन करते हैं कि उन्होंने ऋण/जीटीपी और वित्तीय समझदारी के पथ को अपनी सरकार की घोषित परिधि में रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि हम अपने साधनों से अधिक व्यय न करें और न ही क्षमता से अधिक बोझ डालें।

भारत के रिकॉर्ड निर्यात प्रदर्शन की प्रत्येक स्थान पर भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है और बहुतों ने भारत के उत्प्लावक निर्यात प्रदर्शन का लक्ष्य मन में पाल रखा है। इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। 2021-22 में सेवा क्षेत्र का निर्यात 25,000 करोड़ डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 21.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा। 2021-22 में भारत का कुल निर्यात (व्यापार व सेवा मिलाकर) 34.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 66,965 करोड़ डॉलर पहुंच गया। लौह और इस्पात के निर्यात का मूल्य 2013-2014 के 7.64 अरब डॉलर की तुलना में 2021-2022 में बढ़कर 19.25 अरब डॉलर हो गया है। इसी प्रकार, 2013-14 के बाद पिछले 8 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ट्रैक्टरों के निर्यात में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 के 1300 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के निर्यात की तुलना में 2021-22 में लगभग 43,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात किए गए।

भारत सरकार ने वृहद अर्थशास्त्र के सुदृढ़ सिद्धांतों के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा है और भारत की यह आर्थिक सुदृढ़ता निवेशकों की भावनाओं में पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है। पंजीकृत निवेशकों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अपने घरेलू समकक्षों के जैसे, विदेशी निवेशकों ने भी बड़े परिमाण में निवेश करके भारत में विश्वास व्यक्त किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2021-22 में 83.50 अरब डॉलर के उच्च स्तर को छू गया। 2014 से पहले 2013-14 में एफडीआई मात्र 36.50 अरब डॉलर था।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए ऋणों में 2021-22 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साख वृद्धि को महामारी के पहले वाली स्थिति में लाने में सफलता मिली और यह उत्साहजनक संकेत है, जिससे समग्र आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है। भविष्य के अवसरों और 'न्यू इंडिया' के निर्माण को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं; जैसे कि बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं। ये योजनाएं व्यापक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर, कपड़ा, एलईडी लाइट और ऑटोमोटिव उत्पाद क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की बड़ी क्षमता के साथ 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 करोड़ रुपये की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने इस तथ्य को समझा कि माइक्रो चिपों की आपूर्ति के लिए हम बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। हमें यह उल्लेख करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदीजी ने माइक्रो चिप पर विदेशों की निर्भरता समाप्त करने और आईटी क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में माइक्रो चिप उत्पादन पर बल दिया और इस दिशा में प्रभावी पहल की है।

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत मोदी सरकार ने 3.19 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 1.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बनने से बचाया गया। सरकार के इस प्रयास से देश में 13.5 लाख एमएसएमई को बचाया गया, जो कि भारत के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस योजना ने न केवल लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की, अपितु 1.5 करोड़ रोजगार सृजनकर्ताओं को भी बचाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6 करोड़ लोगों की आजीविका

बची। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जूल 2022 की वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन में कहा है कि मार्च, 2022 में सकल एनपीए अनुपात छह वर्ष के सबसे निचले स्तर 5.9 प्रतिशत पर आ गया है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भविष्य की ओर देखती एक महात्वाकांक्षी परियोजना है। 100 लाख करोड़ रुपए की मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की यह योजना व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही व परिवहन के लिए एक साधन से दूसरे साधन में एकीकृत और निर्बाध संबद्धता देने से साथ एक-दूसरे को जोड़ेगी। इससे अंतिम छोर तक मूलभूत ढांचे की संबद्धता की सुविधा मिलेगी। साथ ही, यह लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा। इस परियोजना के विस्तार से मूलभूत ढांचा क्षेत्र में हजारों रोजगार व नौकरियां उत्पन्न होंगी।

प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा कर सरकार में 10 लाख नौकरियां सृजित करने का वचन दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 'मिशन मोड' में भर्ती करने की घोषणा से रक्षा, रेलवे और राजस्व जैसे क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों को सहायता मिलेगी। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित अग्निपथ योजना न केवल सशस्त्र बलों में सम्मिलित होने और राष्ट्र की सेवा करने के उनके सपने को पूरा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी, अपितु उन्हें सशक्तीकरण, अनुशासन और कौशल भी प्रदान करेगी।

सरकार ने पिछले आठ वर्षों में उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखी है। हाल ही में, जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव देखा गया, वहीं थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में मापी गई मुद्रास्फीति, भू-रणनीतिक अनिश्चितताओं के कारण, आंशिक रूप से अस्थिर रही है। मोदी सरकार ने उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए ठोस उपाय किए हैं।

'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' के विचार से प्रस्तुत किये गए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की प्रशंसा भारत के इतिहास में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में हुई है। देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान कर लगाने के लिए जीएसटी ने करों की बहुलता और नकारात्मकता को समाप्त किया है। यह अर्थव्यवस्था के विकास का एक अच्छा उपाय है और संतोष की बात यह है कि जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। लेखा परीक्षण और विश्लेषण के सराहनीय प्रयासों से करवंचना (कर चोरी) करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिससे कर अनुपालन संस्कृति बन रही है। यह महत्वपूर्ण होगा कि इसको आगे बढ़ाते हुए कर अनुपालन संस्कृति में सुधार और गति बनाए रखी जाए।

गरीबी उन्मूलन

कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 25 महीने तक निःशुल्क अनाज (राशन) दिया गया। यह योजना अप्रैल 2020 से चलाई जा रही है और यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपए व्यय किए हैं और अगले छह मास में सितंबर 2022 तक अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पीएमजीकेएवाई ने घोर निर्धनता को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने भी योजना की इस भूमिका को स्वीकार किया है।

कृषक समुदाय का उत्थान और जीवन स्तर में सुधार हमारे प्रधानमंत्री मोदीजी की सर्वाधिक प्राथमिकता में है। किसान सम्मान निधि योजना गेम चेंजर है। इसके अंतर्गत 11.78 करोड़ किसानों को 10 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में 1.82 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 2009-2014 (मनमोहन सरकार) के पांच वर्ष में देश के कृषि बजट में नाममात्र की 8.5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। जबकि श्री नरेन्द्र मोदीजी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 2014 से 2019 के बीच कृषि बजट में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा मोदी सरकार की किसान हितैषी मंशा, नीति और नेतृत्व का साक्ष्य है।

कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 25 महीने तक निःशुल्क अनाज (राशन) दिया गया

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आर्थिक लाभ

दशकों से सरकारें जटिल वितरणात्मक न्याय एवं अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए आधे-अधूरे मन से प्रयास कर रही थीं। भाजपा सरकार ने नीति-निर्माण को समाज के सबसे निर्धन वर्गों को समावेशित करने पर केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदीजी देश के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वच्छता जैसे विषयों पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। यह विषय ग्रामीण जनसंख्या की भलाई के लिए केंद्रित है। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, सौभाग्य और जल जीवन मिशन जैसी राष्ट्रव्यापी योजनाओं की डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन ने यह सुनिश्चित किया है कि लाखों निर्धन लोगों का जीवन मौलिक रूप से परिवर्तित हो। उनके जीवन स्तर में कई गुना सुधार हुआ है।

'जल जीवन मिशन' का उद्देश्य सभी घरों में नल से जल पहुंचाना है। यह मिशन 'जीवन की गुणवत्ता' को उत्तम बनाने के लिए पूरे वेग से कार्य कर रहा है। यह मिशन उन महिलाओं के लिए 'जीवन की सुगमता' में वृद्धि कर रहा है जो जल एकत्र करने के लिए हर दिन

लंबे, थकाऊ घंटे बिताती हैं। देश के 83 जनपद पहले ही 'हर घर जल' जनपद बन चुके हैं। पिछले दो वर्षों में नल के पानी के कनेक्शन वाले परिवारों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। इस प्रकार देश में नल के पानी के कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या लगभग 17 प्रतिशत से बढ़कर 47.19 प्रतिशत हो गई है। जब यह मिशन 2024 तक पूरा होगा, देश के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल, नल कनेक्शन का पानी होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रियायती एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं। इस प्रकार महिलाओं को एक सुविधा के स्वामित्व के माध्यम से अधिक सम्मान प्रदान किया गया। उज्ज्वला योजना महिलाओं को धुआं मुक्त वातावरण प्रदान करती है और ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम को कम करती है, जिससे उनका समय और स्वास्थ्य बचता है। 2022-23 के बजट में एलपीजी के लिए कम सब्सिडी आवंटन करने की आवश्यकता लगी, जिससे यह उत्साहजनक संकेत मिलता है कि भारत में एलपीजी पैठ में लगभग 99 प्रतिशत संतुष्टि है। ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली घोषणा की दिशा में ये कदम दूरगामी परिणाम देने वाला है।

आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएं परिवारों को स्वास्थ्य गरीबी के जाल में गिरने से बचा रही हैं। इन दोनों योजनाओं की उपलब्धि को कम नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये उपचार के बजाय रोकथाम करती हैं। आयुष्मान भारत सबसे गरीब 50 करोड़ भारतीयों को प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुरक्षा की गारंटी देता है।

वित्तीय और डिजिटल समावेशिता

प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल इंडिया के शुभारंभ के साथ वित्तीय और डिजिटल समावेशिता को शीघ्रता के साथ स्थापित किया गया था। सभी जनधन बैंक खातों में 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं। जनधन योजना से 24.42 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। नाबार्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बैंक से जुड़े 1.1 करोड़ स्वयं सहायता समूहों में से 97 लाख विशेष महिला स्वयं सहायता समूह हैं। अपने इन महिलाओं का स्वयं के बैंक खातों पर नियंत्रण के साथ बैंकिंग उपकरणों की श्रृंखला तक पहुंच है।

जेएएम (जैम) ट्रिनिटी, अर्थात जनधन खाता, आधार और मोबाइल एक साथ, महिलाओं को बड़ी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं। कोविड-19 के कठिन समय में इन प्रभावशाली और राष्ट्रीय स्तर पर निष्पादित नीतियों का बड़ा लाभ देखा गया। जनधन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से महिलाओं को (तीन महीने तक 500 रुपए प्रतिमाह) 30,944 करोड़ रुपये वितरित किए गए। जेएएम ट्रिनिटी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 400 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलियों और सहवर्ती शाखा के सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित हो। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक निःशुल्क एलपीजी रिफिल प्रदान किए गए। रीयल-टाइम लेन-देन (ट्रांजैक्शन) की दिशा में भारत ने डिजिटल इंडिया की मौन क्रांति रच डाली है। 2021 में भारत में 4860 करोड़ रीयल-टाइम लेन-देन हुए, जो कि चीन की तुलना में तीन गुना अधिक है और अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस व जर्मनी के संयुक्त रीयल-टाइम लेन-देन से सात गुना अधिक है।

उद्यमिता को प्रोत्साहन

पीएम-स्वनिधि भारत में धरातल पर उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने की अनूठी योजना है। योजना के अंतर्गत 31.90 लाख रेहड़ी-पटरी वालों का ऋण स्वीकृत किया गया। स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं को 30,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 35 करोड़ उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

भारतीय स्टार्ट अप पारिस्थिकी तंत्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और छिपी हुई भारतीय उद्यमशील प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने से जी उठा है। इसका साक्ष्य यह है कि आज बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां अरबों डॉलर की लुभावनी यूनीकार्न श्रेणी में प्रवेश कर रही हैं।

निष्कर्ष

अगला दशक भारत का दशक है और यह लक्ष्य आत्मनिर्भरता के बिना पूरा नहीं होगा। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए देश के गरीबों के उत्थान के प्रति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की प्रतिबद्धता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में कहर बरपाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंद किया। जहां सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विकास पथ पर वापस आने के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत, महामारी के अपने कुशल प्रबंधन, सुविचारित नीतिगत प्रतिक्रिया, प्रो-एक्टिव् प्रो-रेस्पोंसिव और प्रो-पुअर नीति और इसके त्वरित क्रियान्वयन के कारण, इससे उबर कर प्रगति व विकास की नई कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ा है।

भारत महामारी के अपने कुशल प्रबंधन और के कारण ठीक होने के पथ पर है। आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 8.2 प्रतिशत होगी। उभरती अर्थव्यवस्थाओं सहित विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में यह सबसे आशाजनक विकास अनुमान है। केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अपने सभी प्रयास और ऊर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सही स्थान पुनः दिलाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ■

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

गत आठ वर्षों में अविश्वसनीय उपलब्धियां, व्यापक परिवर्तन

राजनीतिक प्रस्ताव

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 02-03 जुलाई, 2022 को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का समर्थन कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई और असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण तक, हर ओर भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार का भारी जनादेश देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील एवं करिश्माई नेतृत्व में भाजपा को दे रही है, उससे देश में पिछले तीन दशकों की राजनैतिक अस्थिरता का दौर समाप्त हुआ है। भाजपा के पक्ष में यह अद्भुत जनसमर्थन देश में एक नए राजनैतिक युग का शंखनाद कर रहा है। आज केंद्र के साथ-साथ देश के 18 राज्यों में भाजपा-एनडीए शासन में है, जो देश के भाजपा पर बढ़ते हुए विश्वास को प्रतिबिंबित करता है।

हम यहां राजनीतिक प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत की पिछले आठ वर्षों की यात्रा हर स्तर पर अद्भुत उपलब्धियों, व्यापक परिवर्तनों एवं अविस्मरणीय कार्यों से भरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत जबरदस्त आत्मविश्वास से भरकर वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरा है। चाहे वह कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर हो, किसी भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा हो या कहीं युद्ध ही हो रहा हो, भारत हर देश के साथ उसके संकट काल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिस प्रकार से भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अन्य देशों की सहायता की, उसकी सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है।

देश सुशासन एवं विकास के रास्ते पर 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' के नए मानदंडों को स्थापित कर तीव्र गति से आगे चल पड़ा है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का संकल्प सिद्ध हो रहा है तथा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' का मंत्र हर किसी को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में योगदान करने को प्रेरित कर रहा है। पूरे देश ने एक बड़ी करवट ली है। चुनाव दर चुनाव भाजपानीत एनडीए को जनादेश मिला है तथा 2019 के आम चुनावों में देश की जनता ने 2014 से भी बड़ा आशीर्वाद भाजपानीत एनडीए को दिया है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र अपने विराट लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीब, शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्गों के कल्याण तथा महिला एवं युवा सशक्तीकरण पर बल देते हुए केंद्रित किया है जिसका परिणाम यह है कि अनेक अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से इन वर्गों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है। इन जनकल्याण कार्यक्रमों के केंद्र में ग्रामीण जीवन, कृषि, किसानों एवं मजदूरों को रखकर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा का सहभागी बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के दौर में भी 'गरीब कल्याण अन्न योजना' शुरू कर गरीब से गरीब के लिए भी भोजन सुनिश्चित किया गया। साथ ही महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों एवं प्रवासी मजदूरों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि 'मेड इन इंडिया' टीका हर नागरिक को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, जिससे महामारी पर नियंत्रण मिलने में सफलता मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुस्पष्ट एवं संकल्पित नेतृत्व में देश ने हर चुनौती का समाधान पाने में सफलता प्राप्त की है। गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण से लेकर हर क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास एवं मजबूती से उभरते भारत का चित्र— चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र हो, जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र हो, स्टार्टअप्स, रक्षा या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो— भारत हर ओर अपनी एक मजबूत स्थिति दर्ज करने में सक्षम हुआ है। आज जब 'आत्मनिर्भर भारत' का पथ प्रशस्त हो रहा है, एक नया भारत उभर रहा है।

देशभर में भाजपा का बढ़ता जनसमर्थन

पूरे देश में भाजपा को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों में पुनः प्रतिबिंबित हुआ है। जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से चार राज्यों के चुनावों में भाजपा को न केवल विजयश्री प्राप्त हुई है, बल्कि शासन में रहे दल के पुनर्निर्वाचन का इतिहास भी बना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर एवं गोवा में पूर्ण बहुमत से पुनः भाजपा सरकारें निर्वाचित कर मतदाताओं ने राजनैतिक स्थिरता का संकेत दिया है।

उत्तर प्रदेश में कई दशकों में यह पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया और किसी दल की सरकार पुनः निर्वाचित हुई है और वह भी दो तिहाई से भी अधिक बहुमत से। उत्तराखंड में हर पांच वर्ष में सरकार बदलने का क्रम तोड़ते हुए जनता ने प्रदेश की भाजपा सरकार को पुनः एक बड़ा जनादेश दिया है। मणिपुर में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से पुनः निर्वाचित हुई है तथा गोवा में इस बार मतदाताओं ने स्पष्ट जनसमर्थन देकर भाजपा की सरकार बनाई है।

पूरे देश में भाजपा को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों में पुनः प्रतिबिंबित हुआ है। जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से चार राज्यों के चुनावों में भाजपा को न केवल विजयश्री प्राप्त हुई है, बल्कि शासन में रहे दल के पुनर्निर्वाचन का इतिहास भी बना है

पंचायत से पार्लियामेंट तक, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण तक, हर ओर भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद् में सभी 26 सीटें जीत कर भाजपा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी प्रकार हरियाणा में 46 नगर निगमों के चुनावों में 25 सीट पर भाजपा-जेजेपी गठबंधन ने विजय प्राप्त की है। तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनावों में भी नगर निगम चुनाव में 22 सीटें, नगरपालिका में 56 तथा जिला पंचायत में 230 सीटें जीतते हुए 308 सीटों पर भाजपा को अप्रत्याशित विजय मिली है तथा भाजपा तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के विधान परिषद् चुनावों में भाजपा को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। हाल के राज्यसभा चुनावों में भी भाजपा को आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। साथ में लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली है।

जिस प्रकार का भारी जनादेश देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील एवं करिश्माई नेतृत्व में भाजपा को दे रही है, उससे देश में पिछले तीन दशकों की राजनैतिक अस्थिरता का दौर समाप्त हुआ है। भाजपा के पक्ष मे यह अद्भुत जनसमर्थन देश में एक नए राजनैतिक युग का शंखनाद कर रहा है। आज केंद्र के साथ-साथ देश के 18 राज्यों में भाजपा-एनडीए शासन में है, जो देश के भाजपा पर

बढ़ते हुए विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से दूर एवं जनसंख्या की दृष्टि में भिन्न इन प्रदेशों में इस प्रकार के जनसमर्थन से यह स्पष्ट है कि सुशासन, विकास एवं 'परफॉर्मेंस' की राजनीति अब भारतीय राजनीति के हृदय में अपना स्थान बना चुकी है। इस अद्भुत जनसमर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती है एवं देशवासियों को आश्वस्त करती है कि हम जनाकांक्षाओं को निश्चत रूप से पूरा करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत

गुजरात दंगों पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से 'सत्यमेव जयते' का घोषवाक्य पुनः एक बार सत्य सिद्ध हुआ है। यह अब पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत गुजरात दंगों पर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाने के कुप्रयास हुए। इसमें कांग्रेसनीत विपक्ष के प्रतिशोध की राजनीति के अंतर्गत कुछ तथाकथित एनजीओ एवं बुद्धिजीवी और यहां तक कि विदेश से संचालित मीडिया का एक वर्ग एवं इनका पूरा 'इकोसिस्टम' तक शामिल थे। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने झूठे आरोपों, निराधार आक्षेपों एवं कई प्रकार के दुष्प्रचारों को बरसों तक सहते हुए कभी भी भारतीय संविधान, न्याय प्रक्रिया एवं देश की न्यायिक व्यवस्था पर से अपना विश्वास नहीं डिगने दिया और अंततः वे हर प्रकार की अग्निपरीक्षा से अक्षुण्ण होकर बाहर निकले हैं। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने वर्षों तक जिस प्रकार राजनीतिक सहिष्णुता, सहनशीलता, परिपक्वता, उदारता तथा लोकतंत्र एवं संविधान के प्रति आस्था का प्रदर्शन किया है, वह भारतीय समाज जीवन में एक उदाहरण है। इसके लिए भाजपा की यह कार्यकारिणी उनका अभिनंदन करती है।

ध्यान देने योग्य है कि इसके पूर्व भी हर स्तर के न्यायालयों, चाहे वह जिला स्तर हो, उच्च न्यायालय हो या अब सर्वोच्च न्यायालय, हर स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी बेदाग साबित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी बेनकाब हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय ने इन षड्यंत्रकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करती है तथा दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का समर्थन करती है। साथ ही, यह कार्यकारिणी राजनीतिक दुर्भावना एवं प्रतिशोध से ग्रसित ऐसी षड्यंत्रकारी राजनीति की कड़ी भर्त्सना करती है तथा कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों से मांग करती है कि वे पूरे राष्ट्र से इस षड्यंत्रकारी राजनीति के लिए क्षमा याचना करें।

कांग्रेसनीत विपक्ष की नकारात्मक राजनीति

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दल वर्षों सत्ता में रहा आज भारत के संविधान के तहत परिकल्पित रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहा है। अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल झूठ और फरेब की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें न तो भारत के संविधान पर भरोसा है, न देश की जनता पर विश्वास है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों में इनकी आस्था है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं तथा सिद्धांतहीन, अवसरवादी एवं भ्रष्ट राजनीति का शिकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर रचनात्मक कदम का विरोध कर, संसद से पारित कानूनों के रास्ते में रोड़ा अटकाकर तथा सड़कों पर भीड़तंत्र की राजनीति को बढ़ावा देकर वे देश के विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेसनीत विपक्ष लगातार जनता का विश्वास खोता जा रहा है।

एक ओर जहां पूरा राष्ट्र कोविड-19 वैश्विक महामारी का एकजुट होकर सामना कर रहा था, वहीं कुछ विपक्षी राजनैतिक दल झूठे प्रोपगेंडा एवं आधारहीन आरोपों के आधार पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार से कांग्रेस एवं कई अन्य विपक्षी दलों ने भय, शंका एवं नकारात्मकता का वातावरण बनाकर राष्ट्र का मनोबल तोड़ने के प्रयत्न किए, उसे देश कभी भूल नहीं सकता। एक कठिन दौर में इन लोगों ने राष्ट्र की क्षमता को चुनौती दी तथा 'मेड इन इंडिया' टीकों पर झूठे प्रश्न खड़े किए। जब भी देश पर कोई संकट आया या राष्ट्रहित में कोई कार्य सिद्ध किए गए, कांग्रेस और इसके सहयोगियों ने प्रश्न खड़े किए। चाहे सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, एयर स्ट्राइक का विषय हो या फिर सीमा पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम का क्षण हो, कांग्रेस एवं इसके सहयोगी हमेशा विपरीत ध्रुव पर खड़े दिखाई देते हैं। आज जब जांच एजेंसियों द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं इसके पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ की जाती है तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करती है, यदि कोई राष्ट्रहित का विषय भी हो तो कांग्रेस पार्टी देश का ही विरोध करती नजर आती है। परिवारवाद-वंशवाद की राजनीति के कारण कांग्रेस आज सिद्धांतहीन, अवसरवादी एवं भ्रष्ट राजनीति की पर्याय बन गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र की गरिमा नहीं समझ सकती। कांग्रेस स्वयं को हताशा में अपने विनाश की ओर धकेल रही है। हताशा एवं निराशा में कांग्रेस आज देश में विभाजनकारी तत्वों से मेलजोल कर 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के साथ खड़ी दिखती है तथा देश में विष वमन एवं कुप्रचार

> गुजरात दंगों पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से 'सत्यमेव जयते' का घोषवाक्य पुनः एक बार सत्य सिद्ध हुआ है। यह अब पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत गुजरात दंगों पर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाने के कुप्रयास हुए

के माध्यम से भ्रम फैलाना चाहती है। जहां पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपने बयानों में कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्यों का सहारा लेता है, वहीं कांग्रेस के नेता कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र का मामला बताने से भी नहीं कतराते हैं। इनके कई वक्तव्य दूसरे देशों को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने को उकसाते हैं तथा भारत की संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न खड़े करते हैं।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई विपक्ष-शासित राज्यों में 'आयुष्मान भारत' जैसी जन-केन्द्रित केन्द्रीय योजनाओं को या तो लागू नहीं किया जा रहा या उनके क्रियान्वयन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आज सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चलने वाले राजनीतिक दलों के लिए भी परिवारवाद खतरा बना हुआ है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के कई राजनीतिक दल भी परिवारवाद, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद की अलोकतांत्रिक राजनीति की भेंट चढ़ चुके हैं।

सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व: भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन

वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए श्री रामनाथ कोविंद का नामांकन और अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भाजपा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी कमजोर एवं पिछड़े समुदायों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व एवं सशक्तीकरण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

भाजपानीत एनडीए गठबंधन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद का प्रत्याशी बनाकर देश की समस्त महिला एवं जनजातीय समाज का सम्मान किया है तथा सर्वसमावेशी राजनीति के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है

भाजपानीत एनडीए गठबंधन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद का प्रत्याशी बनाकर देश की समस्त महिला एवं जनजातीय समाज का सम्मान किया है तथा सर्वसमावेशी राजनीति के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में गरीबी एवं विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करते हुए सार्वजनिक जीवन में कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए गरीब, वंचित, पीड़ित एवं उपेक्षितों की सेवा कर समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे नारी शक्ति की प्रतिबिंब तो हैं ही, साथ ही इस देश के दबे, कुचले एवं पीड़ित समाज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव, संवेदनशीलता एवं कार्यक्षमता से राष्ट्रपति पद निश्चित सुशोभित होगा।

भारतीय जनता पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के सभी राजनीतिक दलों एवं राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों से अपील करती है कि वे एकजुट होकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें तथा देश की पहली अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब देश के जनजाति समाज से एक महिला राष्ट्रपति चुनने का सौभाग्य हम सबको पहली बार प्राप्त हो रहा है। यह पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का पल है। आइए, इस यज्ञ में हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

सर्वसमावेशी शासन एवं गरीब कल्याण

हाल ही में देश भर में 'सामाजिक न्याय पखवाड़ा' मनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाज के गरीब से गरीब, शोषित, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों की सेवा के प्रति अपने संकल्प को और भी अधिक सुदृढ़ किया है। भाजपा शुरू से ही 'अंत्योदय' के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रही है और इस बात में इसका अटूट विश्वास है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के बिना देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। महिला, युवा, अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के नए अवसर मिल रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए स्वाभिमान एवं न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। भाजपा ने न केवल सेवा के संकल्प को और भी अधिक सुदृढ़ किया, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्तरों पर भागीदारी की।

पिछले आठ वर्षों में देशभर में बिजली, पेयजल, शौचालय, गैस सिलेंडर, बैंक खाता और मोबाइल फोन समाज के हर वर्ग की पहुंच में आ गए हैं, जिससे लोगों के जीवनस्तर में भारी सुधार हुआ है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच देश में अत्यधिक गरीबी में कमी मोदी सरकार के गरीब कल्याण कार्यक्रमों की उपलब्धियों का द्योतक है। उज्ज्वला, जनधन, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटिड यूरिया, लागत से डेढ़ गुणा एमएसपी, एमएसपी के अंदर रिकार्ड खरीदी एवं अनेक नए फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन जैसी अनेक योजनाएं आज गरीब से गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला रही हैं। इन योजनाओं से महिला, युवा, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित-पीड़ित एवं कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण हुआ है।

भारत की उपलब्धियों को यदि पिछले दो वर्षों के कोविड-19 महामारी के संदर्भ में यदि देखें; जबकि वैश्विक स्तर पर कई समस्याएं खड़ी हुईं; तब यह उपलब्धियां अद्भुत एवं अभूतपूर्व लगती हैं। यह एक ऐसा चुनौतीपूर्ण दौर रहा जिसका सामना करना अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत एवं दृढ़-निश्चयी नेतृत्व में देश ने हर चुनौती को अवसर में बदला तथा कई जरूरतमंद देशों के कठिन समय में उनका सहयोग

किया। इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने के भारत के दृढ़ संकल्प का साक्षात्कार पूरे विश्व ने किया, जब देश में 'मेड-इन-इंडिया' टीकों का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के सबसे व्यापक एवं तेज टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश के 95 प्रतिशत से अधिक पात्र नागरिकों को टीके की कम-से-कम एक खुराक दी जा चुकी है। जहां कांग्रेसनीत विपक्ष यह दावा कर रहा था कि पूरे देश में 15 वर्षों में भी टीकाकरण पूर्ण नहीं हो सकता, वहां मात्र डेढ़ वर्षों में लगभग 200 करोड़ टीकों की खुराक देकर देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतना ही नहीं, इन टीकों को कई अन्य जरूरतमंद देशों को उपलब्ध कराकर आज इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में भारत एक अग्रणी भूमिका में है। पिछले दो वर्षों से निःशुल्क राशन, निःशुल्क टीका, समाज के कमजोर वर्गों को सहायता एवं राहत, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा 'सेवा ही संगठन' अभियान के माध्यम से देशभर में व्यापक जनसेवा, चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्साकर्मियों, प्रशासनकर्मियों एवं कोरोना योद्धाओं द्वारा समाज की निःस्वार्थ सेवा, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान एवं इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए असंख्य अभिनव एवं मजबूत पहल से जन-जन का विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व कौशल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की निःस्वार्थ सेवा पर और भी अधिक सुदृढ़ हुआ है। आज देश की जनता का इन उपलब्धियों से न केवल मस्तक ऊंचा हुआ है, बल्कि वे देश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं।

पिछले 8 वर्षों में भारत ने न केवल लंबे समय से चली आ रही विभिन्न समस्याओं को निर्णायक रूप से हल किया है, बल्कि 21वीं सदी में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक ऐतिहासिक सुधार भी किए हैं

विश्व पटल पर उभरा भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, जापान एवं यूएई की यात्रा, भारत-नॉर्डिक सम्मेलन, क्वाड तथा जी-7 में लिए गए निर्णय से संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। साथ ही, इन यात्राओं से भारत के नए क्षेत्रों में भागीदारी के लिए सक्रिय प्रयासों का परिणाम भी सामने आया। भारत की विदेश नीति में प्रवाहित होती यह नई ऊर्जा देश के वैश्विक दायित्वों के निर्वहन करने की तत्परता एवं विभिन्न देशों के साथ बहुस्तरीय भागीदारी में परिलक्षित हो रही है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उदय हो रहे एक नए भारत का उद्घोष है जो 'शीत युद्ध' के साये से बाहर निकल चुका है और बिना किसी हिचक के हर देश से सकारात्मक संबंध बनाने को प्रयासरत है। यूरोपीय देशों के साथ भागीदारी से आने वाले दिनों में भारत के लिए संभावनाओं के अनेक द्वार खुलेंगे तथा भागीदारी करने वाले देशों की भी अनेक आवश्यकताएं पूरी होंगी।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के पिछले दो वर्ष के दौरान भारत विश्व के एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। भारत ने न केवल इस महामारी की चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया, बल्कि अन्य देशों को भी उनके संकट के समय में दवाइयां, पीपीई किट ऑक्सीजन, कोविड-रोधी टीके एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता की। जिस प्रकार से रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से विश्व के अनेक नेताओं ने अपील की तथा दोनों देशों से कुछ समय के युद्धविराम की छूट प्राप्त कर युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकाला गया, उससे अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत के बढ़ते हुए कद का आभास होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता के अलावा, भारत ने कॉप-26 में जलवायु परिवर्तन पर पांच प्रतिबद्धताओं पर भी तेजी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भारत की पहल पर 'अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन' की स्थापना की पूरे विश्व में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ नेतृत्व में भारत आज वैश्विक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है और पूरे विश्व के लिए आशा की एक नई किरण बनकर उभर रहा है। पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है तथा विदेश में बसे भारतवंशियों का गौरव बढ़ा है एवं वो देश से जुड़ा महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन देशों के साथ हुए समझौतों से यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं जी-7 के अन्य देशों के साथ भारत की एक लंबी भागीदारी की शुरुआत हुई है तथा संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं।

'नए भारत' का संकल्प

पिछले 8 वर्षों में भारत ने न केवल लंबे समय से चली आ रही विभिन्न समस्याओं को निर्णायक रूप से हल किया है, बल्कि 21वीं सदी में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक ऐतिहासिक सुधार भी किए हैं। कांग्रेसनीत यूपीए के कुशासन, भ्रष्टाचार, घपलों एवं घोटालों को देश आज भी भूला नहीं है। यह वह दौर था जब हर दिन कोई न कोई घोटाला समाचार-पत्रों की सुर्खियां बना रहता था और 'पॉलिसी पैरालिसिस' जैसे शब्द सरकार के शब्दकोश की पहचान बन गए थे। एक दिशाहीन एवं नेतृत्वविहीन सरकार केंद्र में थी। पूरे देश में निराशा एवं हताशा का वातावरण था। ऐसे समय में पूरे देश ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट जनादेश दिया। आज, आठ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश में एक नई कार्य-संस्कृति का शुभारंभ हुआ है जिसके कारण भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन आज जन-जन को प्राप्त हो रहा है।

प्रधानमंत्रीजी के अथक प्रयासों के कारण आज 'प्रगति' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की निरंतर समीक्षा करते हुए उनको गति दी जा रही है तथा वर्षों से लटकी परियोजनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। पिछली सरकारों की कार्यशैली से विपरीत कई परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पूर्व ही पूरी की

गई हैं। इसका परिणाम हम वर्षों से लटकी बोगीबील ब्रिज, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अटल टनल जैसी परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन में देख सकते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। देश में विकास एवं सुशासन जन-जन को सुलभ हो इसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों से निरंतर संवाद कर 'सहकारी संघवाद' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। इसका सबसे प्रभावी परिणाम कोरोना महामारी को देशभर में नियंत्रित करने में मिली सफलता के रूप में देखा जा सकता है। यहां तक की पद्म पुरस्कारों का भी पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण किया गया है, तथा पूरे देश में छिपी हुई प्रतिभाओं एवं देशहित में अनूठे कार्य करने वालों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया गया है।

नए भारत की नई कार्य-संस्कृति का ही परिणाम रहा कि भारत ने जीएसटी जैसे बड़े कर सुधार को अपनाया। विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आज जीएसटी परिषद हर निर्णय सर्वसम्मति से लेकर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का पूरे विश्व में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। आज जीएसटी को देश की जनता ने भी पूरी तरह से अपनाया है, जिसका परिणाम हम हर महीने रिकॉर्ड कर संग्रह में देख सकते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जनता को कई प्रकार के करों के जंजाल से मुक्ति मिली है और अंतर्राज्यीय व्यापार सुगम हुआ है। इसके अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान भी राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का केंद्र द्वारा निरंतर भुगतान किया गया है। धारा 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करने, तीन तलाक पर कड़े कानून बनाने, वन रैंक-वन पेंशन लागू करने, राष्ट्रीय समर स्मारक तथा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना, बोड़ो एवं ब्रू-रियांग समझौते जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गतिशक्ति, पीएलआई, हरित हाइड्रोजन, जैविक खेती को प्रोत्साहन, कार्य-संस्कृति में सुधार, डिजीटल इंडिया मिशन, खेलकूद को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया एवं अग्निपथ जैसे अनेक सुधार कार्यक्रमों से एक नए भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

भारतीय जनता पार्टी देश की महान जनता से यह आह्वान करती है कि वह परिवारवाद-वंशवाद, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद की विभाजनकारी, अवसरवादी, सिद्धांतहीन एवं भ्रष्ट राजनीति को पूरी तरह से परास्त करे

आह्वान

आज जबकि आत्मविश्वास से भरे एक ऐसे देश का उदय हो रहा है जिसके मन में 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प है, हर ओर एक नई प्रकार की ऊर्जा देखी जा सकती है। एक ऐसा भारत जो कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौतियों का न केवल सफलतापूर्वक सामना करता है, बल्कि अन्य देशों को इस कठिन घड़ी में सहायता भी करता है, एक 'नए भारत' की शक्ति को दर्शाता है। एक भारत जो कोविड-रोधी टीकों का निर्माण कर सकता है, जो हर महामारी में चुनौती को विभिन्न सुधारों के माध्यम से अवसर में बदल सकता है जो पिछले दो वर्षों से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे सकता है, महामारी में समाज के कमजोर वर्गों की चिंता कर सकता है और हर व्यक्ति को निःशुल्क टीका दे सकता है। यह भारत आज से मात्र आठ वर्ष पूर्व यूपीए के कुशासन के दौर में असंभव दिखता था। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कुशल नेतृत्व है जिसने करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं देशभर में जन-जन को निःस्वार्थ राष्ट्र सेवा के लिए अपने अथक प्रयासों एवं स्वयं के उदाहरण से प्रेरित किया, उसके कारण ही संभव हो पाया है। आज एक ऐसे भारत का उदय हुआ है जो अब किसी क्षेत्र में पिछड़ता नहीं, बल्कि हर कार्य को लक्ष्य कर समय से पहले पूर्ण कर लेता है। आज जब भारत अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान रहा है, 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य अब दूर नहीं है।

महाराष्ट्र के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रुप में समर्थन दिया है तथा भाजपा की ओर से श्री देवेन्द्र फडणवीस ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश में 'महाविकास अघाड़ी' के अवसरवादी एवं सिद्धांतहीन गठजोड़ के कारण महाराष्ट्र का विकास अवरुद्ध हुआ तथा जनता को भारी भ्रष्टाचार एवं कुशासन का सामना करना पड़ रहा था। इस कदम ने एक बार पुनः प्रमाणित कर दिया है कि भाजपा पद की नहीं, बल्कि जनसेवा एवं जनकल्याण की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता की सेवा के परम लक्ष्य के साथ हम पुनः प्रदेश को विकास एवं सुशासन के मार्ग पर तीव्र गति से आगे ले जाएंगे।

स्वतंत्रता के पश्चात् भाजपा एकमात्र ऐसे दल के रूप में उभरी, जिसने लोकतंत्र एवं जनहित में अनेक सुधारों की मांग एवं उनका समर्थन किया तथा शासन में आने पर इन्हें कार्यान्वित किया, ताकि देश की लोकतांत्रिक पद्धतियां और भी अधिक सुदृढ़ हो सकें। एक ऐसे राजनैतिक दल के रूप में जो देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेता हो, भाजपा देश में सुदृढ़ अवसंरचना, युवाओं के लिए अपार संभावनाएं एवं भविष्योन्मुखी नीतियों के माध्यम से हर क्षेत्र के विकास के साथ 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। आज देश भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ रहा है तथा कांग्रेसनीत विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को चुनाव दर चुनाव पराजित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की महान जनता से यह आह्वान करती है कि वह परिवारवाद-वंशवाद, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद की विभाजनकारी, अवसरवादी, सिद्धांतहीन एवं भ्रष्ट राजनीति को पूरी तरह से परास्त करे और विकास, सुशासन एवं 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस' को और भी अधिक सुदृढ़ करते हुए सर्वसमावेशी एवं गरीब कल्याण की राजनीति के पक्ष में एकजुट हो। ■

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

आज का भारत तुष्टीकरण के कालखंड से आगे बढ़कर तृप्तीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन उद्बोधन

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 जुलाई, 2022 को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से आजादी के अमृत काल में देश को विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। भाजपा की द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूरे सत्र के दौरान कार्यकारिणी सदस्यों को प्रधानमंत्रीजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि आठ साल पहले देश में निराशा, नकारात्मकता, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था, लेकिन जब देश की जनता ने भाजपा में अपना विश्वास जताते हुए भाजपा की सरकार बनाई तो उसके बाद से देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमने जनता के भरोसे को टूटने नहीं दिया। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सात सूत्र बताए। ये सूत्र हैं- सेवाभाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। उन्होंने कहा कि ये सात सूत्र हमारे जीवन से जुड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाने में सफल होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन के मुख्य बिंदु:

- यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश अमृतकाल में अपने लिए नए संकल्प ले रहा है। जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, तब देश जिस ऊंचाई पर होगा, उसके लिए प्रयत्न करने का यही सही समय है। एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अगले 25 वर्षों के लिए अपना एक रोडमैप बनाए तथा भविष्य से जुड़ी नीतियों और निर्णयों पर मंथन करे।
- विपक्षी पार्टियों की स्थिति बहुत खराब है। हमें उनकी इस स्थिति से सीख लेनी है कि वो कौन सी बुराई और कमियां हैं, जिसके कारण वे इतने नीचे आ गए, जनता से दूर होते गए और लगातार दूर होते ही जा रहे हैं। हमें उन चीजों से अपने आप को बचाए हुए रखना है, क्योंकि हम अपने के लिए नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं।
- सत्ता से बाहर होने पर कई पार्टियों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है जबकि भाजपा जिन राज्यों में दशकों तक सत्ता में नहीं थी, वहां भी पार्टी का कैडर रहा, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। हमारे कार्यकर्ता न थके हैं, न झुके हैं और न रुके हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा के कार्यकर्ता देश के लिए अविचल रह कर काम कर रहे हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है।
- आठ साल पहले देश में निराशा, नकारात्मकता, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था लेकिन जब देश की जनता ने भाजपा में अपना विश्वास जताते हुए भाजपा की सरकार बनाई तो उसके बाद से देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमने जनता के भरोसे को टूटने नहीं दिया।
- आज हमारी सरकार की पहचान है— P2G2 अर्थात् Pro-People, Pro-Active Good Governance. जब दुनिया कोरोना के सामने किंकर्तव्यविमूढ़ की सी स्थिति में थी, तब हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे थे। एक समय की निराशा आज आशा, विश्वास, भरोसा और श्रद्धा में बदल चुकी है। आज देश अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से निरंतरता की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत तुष्टीकरण के कालखंड से आगे बढ़ कर तृप्तीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पहले गरीबों को बुनियादी सुविधाओं और आगे बढ़ने के अवसरों के बिना जिस तरह की जिंदगी बितानी पड़ी, उनके बच्चों को उन हालातों से गुजरना नहीं पड़ेगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है— हमें आने वाली पीढ़ियों को आज से बेहतर भविष्य देना है, आज से बेहतर जीवन देना है।
- दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी भी क्यों देश की प्रगति की कोई दिशा तय नहीं कर पाई? आज देश की प्रगति की दिशा भी तय है, संकल्प, सपने भी साथ है। हमारी नीति और नीयत भी समान हैं। आज भारत का संकल्प आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और गरीब कल्याण का है। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। आज का भारत बिना किसी भेदभाव के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के रास्ते पर चल रहा है। प्रगति की यही दिशा देश को विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करेगी।
- युग बदलता है, समय बदलता है, देश बनते हैं, देश कभी रुकता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी भूगोल और इतिहास भी बदलते हैं लेकिन हमारा देश शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहने वाला है।
- जब कोरोना के कारण दुनिया भर में गरीबी बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, तब उस कालखंड में भारत में गरीबी में कमी आई है। यह हमारी नीति और नीयत का परिचायक है। जब पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित कोरोना के कारण प्रभावित हो रही थीं तब हमारा भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है, तब भारत निर्यात में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जब दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन अभी भी एक बड़ी चुनौती है, तब भारत 200 करोड़ वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करने की कगार पर खड़ा है। हमने 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के साथ 23 करोड़ डोज दुनिया के गरीब देशों को पहुंचाए हैं और वहां गरीबों की जिंदगी बचाई है। भारत वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने और उसके समाधान की दिशा में काम कर रहा है।
- आज भारत परिवारवाद की राजनीति और पुरानी मानसिकता से ऊब चुका है। आने वाले दिनों में परिवारवाद की राजनीति करने वाले ऐसे दलों के लिए टिक पाना मुश्किल है। हिन्दुस्तान की जनता अब ऐसी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगी। स्थापना काल से ही हमारी पार्टी की आत्मा में सच्चे लोकतंत्र (true democracy) का संस्कार रहा है। सरदार पटेल ने 'एक भारत' का निर्माण किया। वे कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य हमें मिला। देश के सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाने का साहस भी हम ही कर सकते हैं। देश में जो कुछ उत्तम है, सब हमारे ही हैं - हम इस भावना से काम कर रहे हैं।
- जो वर्षों तक देश की सत्ता पर काबिज रहे, वे देशहित की योजनाओं का भी अंधा विरोध करने पर उतारू हैं। जनता उन्हें न तो सुनती है, न स्वीकारती है, बस नकारती है। नकारात्मकता के बीच सकारात्मक बात को उठाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। हमने गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो काम किये, उन्हें जनता तक पहुंचाना जरूरी है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के

लिए जो प्रयास किये, उसे जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।

- मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सात सूत्र बहुत जरूरी हैं। ये सूत्र हैं— सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। ये सात सूत्र हमारे जीवन से जुड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाने में सफल होंगे।
- भाजपा ने सभी कार्यक्रमों में बहनों को विशेष अवसर दिया है। इस बार की कार्यकारिणी बैठक में मंच संचालन से लेकर प्रस्ताव पेश करने तक में बहनों को भूमिका दी गई है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। इस तरह से कार्यक्रमों की रचना लगातार होनी चाहिए।
- आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज की महिला भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाली हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी समाज को नई पहचान मिल रही है। पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्र के सर्वोच्च प्रदेश पर आसीन होने का सपना साकार हो रहा है।
- 'सबका प्रयास' हमारी हर चीज में होना चाहिए। हमारी विचारधारा और कार्यक्रम एक ही है— नेशन फर्स्ट। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जनता ने हमें स्वीकार किया है, आशीर्वाद दिया है लेकिन अभी भी कुछ टोलियां ऐसी बैठी हुई हैं जो सत्य को आगे पहुंचने में रुकावटें डालती हैं, लेकिन हमें सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी विकास और गरीब कल्याण के काम पर ही आगे बढ़ना है।
- आजादी का अमृत महोत्सव सरकार का, भाजपा का या नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम नहीं है, यह पूरे देश का कार्यक्रम है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के इतर किसी और पार्टी की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में कोई भूमिका नहीं है। यह राजनीतिक असहिष्णुता का परिचायक है।
- हमें 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास' के मंत्र को साकार करते हुए चलना है। भाजपा के विस्तार का मतलब है- एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार! भाजपा के विस्तार का मतलब है— राष्ट्र प्रथम के संकल्प का विस्तार। हमें पहली बार मतदान करने वालों (First Time Voters) को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।
- लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी धरती से हमें 'एक भारत' दिया था। आज हम उसी धरती से 'एक भारत को श्रेष्ठ भारत'बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, उनकी पूरी टीम को और तेलंगाना प्रदेश भाजपा इकाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
- आजादी के अमृत काल में हम हर जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। 25 वर्ष का अमृतकाल देश के उज्ज्वल भविष्य के साथ भाजपा के लिए उज्ज्वल भविष्य लेकर आयेगा। हम एक नए भारत का सपना साकार करने के लिए आगे बढ़ें, यही संकल्प होना चाहिए। हमारा सपना हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है, जन-कल्याण का है। हम सब एक नए भारत के निर्माण का सपना जरूर पूरा करेंगे। ■

श्रद्धांजलि

हिमाचल भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश शर्मा नहीं रहे

हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष और प्रदेश कामगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा (बबली) का 2 जुलाई को निधन हो गया।

श्री शर्मा 47 वर्ष के थे। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में सक्रिय रूप से कार्य किया, जहां से उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया और विद्यार्थी परिषद् के दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, साथ ही उन्होंने अन्य विभिन्न जिम्मेदारियों को भी निभाया।

अध्यक्ष के तौर पर श्री शर्मा ने हाल ही में कामगार बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और पूरे प्रदेश का दौरा भी किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा 'बबलीजी' के निधन की खबर अत्यंत दुःखद हैं। उनका संपूर्ण जीवन समाज व संगठन की सेवा के प्रति समर्पित रहा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना व उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा जी का हृदयाघात के

कारण निधन हो गया है। उनके आकस्मिक निधन से सम्पूर्ण भाजपा परिवार शोकग्रस्त है और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ■

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

तेलंगाना पर प्रेस वक्तव्य

'राज्य की वंशवादी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें'

हैदराबाद (तेलंगाना) में 02-03 जुलाई, 2022 को आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेलंगाना की स्थिति और खराब होने पर चिंता प्रकट की गई। पार्टी द्वारा जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की दयनीय हालत है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। आजीविका की तलाश में लोग राज्य से पलायन कर रहे हैं। किसानों को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है। इन परिस्थितियों में केवल भाजपा, अपने 'देश-प्रथम' दृढ़ विश्वास और ध्यान के साथ तथा भ्रष्टाचार मुक्त और घोटाला मुक्त शासन के त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझ सकती है। हम यहां तेलंगाना पर भाजपा द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तेलंगाना राज्य में आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास से संबंधित सभी मैट्रिक्स और सूचकांकों में गंभीर गिरावट पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। पिछले आठ वर्षों में राज्य ने जो यह घिनौना पतन देखा है, वह दर्दनाक है और इसमें वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी पूरी तरह से है।

भाजपा ने पृथक तेलंगाना के लिए भावनात्मक जन आंदोलन का नेतृत्व किया

पृथक तेलंगाना राज्य के लिए संघर्ष, जैसे हैदराबाद संस्थान की मुक्ति के लिए भारतीय संघ में विलय सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष, भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं, छात्रों और कर्मचारियों ने एक अलग राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबा और उत्साही संघर्ष जारी रखा। उन्हें आबादी के सभी वर्गों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। आंदोलन ने अपने कई चरणों में कई युवाओं के बलिदान को देखा, जिनमें से कुछ का बलिदान अविस्मरणीय है। तेलंगाना के लोगों की सामूहिक इच्छा, भाजपा के रचनात्मक संघर्ष समर्थन ने एक सम्मोहक स्थिति पैदा की, जिसके कारण 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ।

पृथक तेलंगाना राज्य के लिए संघर्ष लोगों की भावनाओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है

जब श्री राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे तब संघर्ष और लोगों द्वारा किए गए बलिदान की सराहना करते हुए वे भाजपा ने 2006 में एक अलग राज्य की मांग का समर्थन किया। इतना ही नहीं, भाजपा ने बाबासाहेब अम्बेडकर के छोटे राज्यों के दृष्टिकोण का समर्थन किया, क्योंकि छोटे राज्य तेजी से विकास करते हैं, बेहतर प्रशासन और सभी समुदायों के गहरे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरदायी हैं। पृथक तेलंगाना से विकास संभव था, जैसाकि अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़,

उत्तराखंड आदि के गठन से यह साबित हुआ है।

यह स्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना आंदोलन ने तब तेजी पकड़ी जब भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ उसमें उतरी। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, जिन्हें तेलंगाना में 'चिन्नम्मा' के नाम से जाना जाता है, ने तेलंगाना राज्य में कई रैलियां कीं और तत्कालीन राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए।

यह स्पष्ट है कि एक अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में भाजपा सबसे आगे थी और उसके सक्रिय और स्पष्ट समर्थन के कारण ही पृथक तेलंगाना संभव हो पाया।

नीलू, निधुलु, नियामकालु - अधूरी आकांक्षाएं

नीलू, निधुलु, नियामकालु (पानी, धन, और रोजगार रिक्तियों को भरना) 1969 में और 2014 में तेलंगाना के गठन तक चले दूसरे चरण में आंदोलन के सर्वोत्कृष्ट पहलू रहे हैं।

हालांकि, अलग तेलंगाना की ऐतिहासिक उपलब्धि के आठ साल बाद राज्य के लोग बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीदों और आशाओं पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। विडंबना यह है कि जिन लोगों ने तेलंगाना के नाम से राजनीतिक लाभ उठाया, वे लोग ही जनता के साथ धोखाधड़ी करने में सबसे आगे रहे। नतीजतन, निराशा की भावना ने तेलंगाना की आम जनता को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या इतने बलिदानों ने अंततः उन्हें इस गिरावट का गवाह बनाया है।

टीआरएस तेलंगाना आंदोलन के तीनों मैट्रिक्स, नील्लू, निधुलु और नियामकालु (पानी, धन और रोजगार रिक्तियों को भरने) पर बुरी तरह विफल रही है

मौजूदा सरकार के आठ साल बाद तेलंगाना की स्थिति और भी खराब हो गई है। भाजपा ने तेलंगाना आंदोलन को एक परिवार की सनक को सौंपने और परिवार को अवैध संपत्ति जमा करने में सक्षम बनाने के लिए समर्थन नहीं किया था। भाजपा ने तेलंगाना का इस आशय से समर्थन किया कि तेलंगाना के लोगों, विशेषकर युवाओं, छात्रों, किसानों और अन्य हाशिए के वर्गों की आकांक्षाओं को साकार किया जाए। भाजपा को उम्मीद थी कि हाशिए पर रहने वाले और युवाओं की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। हालांकि, न तो कोई भर्ती अभियान चलाया गया है और न ही दलितों और महिलाओं जैसे हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई प्रयास किया गया है।

इसके विपरीत अव्यावहारिक योजनाओं पर नोटिफिकेशन जारी करने और दिखावटी घोषणाओं के अलावा आज तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं हुआ है। सत्तारूढ़ सरकार ने अपने 2014 के घोषणापत्र में एक लाख रिक्तियों को भरने का वादा किया था, किंतु वह ऐसा करने में विफल रही। इसी तरह तेलंगाना के विश्वविद्यालय, जिनकी तेलंगाना के गठन में भूमिका अहम और महत्वपूर्ण थी, आज निराशाजनक स्थिति में हैं क्योंकि 70 प्रतिशत संकाय पद खाली हैं और अनुसंधान, विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन की भारी कमी है। शिक्षकों की भर्ती और स्कूल भवनों के पूरी तरह से जर्जर होने से स्कूली शिक्षा की स्थिति और भी खराब है।

तेलंगाना के अस्पतालों की भी हालत दयनीय है। उम्मीद की जा रही थी कि कोविड के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति सरकार के रवैये में व्यापक बदलाव आएगा। सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 70 प्रतिशत रिक्तियां और इस राज्य के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक, अर्थात् उस्मानिया अस्पताल की दयनीय स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति सरकार के लापरवाह रवैये को दर्शाती है।

ऐतिहासिक, आर्थिक आदि कई कारणों से उत्तरी तेलंगाना के लोग आजीविका की तलाश में खाड़ी देशों में चले गए- इसलिए नहीं कि उनके पास वहां भव्य पद थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अधिकांश पुरुष सदस्य अपने परिवार को छोड़कर चले गए। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक लोग, ज्यादातर उत्तरी तेलंगाना से, खाड़ी देशों में चले गए। वर्तमान शासन के नेताओं ने लंबे और ऊंचे दावे किए कि एक बार एक अलग राज्य स्थापित हो जाने पर; वे सभी जो अब तक प्रवास कर चुके थे, वे अवसरों की अधिकता के कारण स्वेच्छा से वापस आएंगे। पिछले आठ सालों में हकीकत में क्या हुआ? पलायन नहीं रुका। इतना ही नहीं, राज्य सरकार खाड़ी में उत्पीड़न का सामना करने वालों को बचाने के लिए भी आगे नहीं आई।

जब 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था तब तेलंगाना भरपूर धन के साथ एक समृद्ध राज्य था। राज्य का राजस्व अधिशेष 369 करोड़ रुपये था जो अब 16,500 करोड़ रुपये का घाटा हो गया है। आज राज्य की देनदारियां चार गुना बढ़कर 3.20 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं।

पानी के मुद्दे पर सरकार के दावों और हकीकत में मेल नहीं है। सरकार का तथाकथित प्रमुख कार्यक्रम, कालेश्वरम धन की हेराफेरी के आरोपों से भरा पड़ा है। तथ्य यह है कि परियोजना की लागत 40,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

दूसरी ओर कलेश्वरम का बहाना बनाकर अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए पालमूर-रंगारेड्डी परियोजना, जो पिछड़े दक्षिण तेलंगाना में 18 लाख एकड़ की सिंचाई के लिए थी, उपेक्षित है। नेट्टम्पाडु, डिंडी, आदि जैसी परियोजनाओं का भी यही हाल हुआ है।

टीआरएस तेलंगाना आंदोलन के तीनों मैट्रिक्स, नील्लू, निधुलु और नियामकालु (पानी, धन और रोजगार रिक्तियों को भरने) पर बुरी तरह विफल रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना के लोगों को लगता है कि वे वर्तमान सरकार के कार्यकाल

के दौरान तवे से सीधे आग में गिर गए हैं। (पेनम लो नुंची पोय्यि लोकी, तवे से निकले चूल्हे में गिरे)।

आधुनिक निज़ाम और उनके रजाकार— एक नए तेलंगाना मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता

पिछले आठ वर्षों के दौरान तेलंगाना ने एक राजवंश को कायम रखने के लिए एक निर्लज्ज और घोर प्रयास देखा। मुख्यमंत्री के बेटे को आज जो शक्ति प्राप्त है, वह अन्य कैबिनेट मंत्रियों से कहीं अधिक है। शासन परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है।

राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। सत्ताधारी दल के नेता, सत्ता में उनके सहयोगी और उनके भाई-बहन जघन्य अपराधों में शामिल हो रहे हैं। विपक्षी दलों पर झूठे मामले थोपने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। विधायक के बच्चे कीचक बन गए हैं और उचित सतर्कता की कमी के कारण ड्रग कल्चर कायम हो गया है। वास्तव में तेलंगाना ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 95.4 है और देश में शीर्ष 5 में से एक है और 56.5 की राष्ट्रीय दर से लगभग दोगुनी है। इसी तरह बच्चों के प्रति अपराध दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 28.9 है।

तेलंगाना में हम जो देख रहे हैं वह सरासर निरंकुशता, बेलगाम भाई-भतीजावाद और शर्मनाक अहंकार है, जिसका तेलंगाना की जनता ने हमेशा विरोध किया है। 1946-48 के तेलंगाना मुक्ति आंदोलन के दौरान लोग रजाकारों के अत्याचारों के खिलाफ थे, जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता को अंजाम दिया। साथ ही, वे स्थानीय जमींदारों की निरंकुशता के भी खिलाफ थे। आज हम तेलंगाना में जो देख रहे हैं वह 1946 के अनुभव की पुनरावृत्ति है। हमारे सामने एक निरंकुशता है और पार्टी कार्यकर्ताओं की आड़ में उनकी मुखौटा सेना है और निश्चित रूप से कासिम रिज़वी (एमआईएम) की संतान निरंकुश मुख्यमंत्री के साथ है और इस तथ्य की व्याख्या कैसे करें कि अधिकांश रोहिंग्या राशन कार्ड सहित सभी लाभ उठा लेते हैं? हम आदिलाबाद जिले के दंगा प्रभावित भैंसा कस्बे में अपराधियों और पीड़ितों के प्रति इस सरकार के रवैये को कैसे समझें जो इस सरकार की तुष्टीकरण नीति का एक उदाहरण है।

दूसरी ओर तेलंगाना सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जिसमें 80 प्रतिशत आबादी हाशिए के समूहों से आती है। यह स्वाभाविक है कि एक सरकार जो इन वर्गों पर अपनी जड़ें जमाने का दावा करती है, उनसे उनके सशक्तीकरण के लिए नीतियां शुरू करने की उम्मीद की जाती है। उनकी स्थितियों में सुधार के लिए किसी भी ठोस कार्यक्रम के अभाव में इन वर्गों को तेलंगाना राज्य में हाशिये पर धकेल दिया जाता है।

इसके अलावा जब केंद्र सरकार ने इस तथ्य की सराहना करते हुए कि गरीबी में न तो वर्ग होता है और न ही जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया। फिर भी तेलंगाना सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिसूचित करने में 2.5 साल से अधिक का समय लगा। अभी भी कार्यान्वयन असंतोषजनक और अधूरा है।

भाजपा एक ऐसा तेलंगाना चाहती थी जहां सभी लोग, विशेषकर युवा, रोजगार के अवसर पाकर और जीवन और आजीविका के निर्वाह में खुश और आनंद से रहें। हालांकि, पिछले आठ वर्षों के दौरान तेलंगाना ने जीवन और आजीविका का पूर्ण विनाश और तबाही ही देखी है।

किसानों को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है। रयितु बंधु के नाम पर अन्य सभी सब्सिडी प्रावधान वापस ले लिए गए हैं। इतना ही नहीं वर्तमान निज़ाम का अत्यधिक असुरक्षित मुखौटा पहने एक मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया है।

इस दयनीय शासन के रिकॉर्ड के कारण और तेलंगाना में वर्तमान स्थिति को एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है: -DY''NASTY'। वंशवादी दलों की यह विशेषता रही है कि यहां परिवार और परिवार ही मायने रखता है। यह अन्य सभी हितों—राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय समुदायों पर पारिवारिक हितों की प्राथमिकता है, जो पिछले आठ वर्षों में राज्य में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार का एकमात्र कारण है।

मोदी सरकार का वादा— तेलंगाना के भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना

दूसरी ओर राज्य सरकार के कठोर रवैये के बावजूद केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। सहकारी संघवाद की भावना से 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग ने 42 प्रतिशत और 41 प्रतिशत क्रमशः केंद्रीय से राज्य करों की सिफारिश की है। परिणामस्वरूप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की उपार्जित राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 और 2022 के बीच नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए पिछले 9 बजटों में लगभग रु. 1.30 लाख करोड़ तेलंगाना राज्य को हस्तांतरित किए गए हैं। परिवर्तन की मात्रा की तुलना के लिए अविभाजित राज्य में 2009 और 2014 के बीच तेलंगाना क्षेत्र का हिस्सा लगभग 30,000 करोड़ रुपये था, जबकि राज्य को मोदी सरकार में 5 वर्षों में 2014 और 2019 के बीच 70,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। पंचायतों के विकास के लिए तेलंगाना में, 15वें वित्त आयोग द्वारा 4,320 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और पहली किश्त के रूप में 820 करोड़ रुपये जारी किए गए।

रामागुंडम उर्वरक कारखाना, जो कांग्रेस शासन के दौरान बंद कर दिया गया था, 2015 में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा फिर से खोला गया। श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इसके संयंत्र के लिए 6,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,511 किलोमीटर थी, यह बढ़कर 4,996 किलोमीटर हो गई। 2022 में 2,485 किलोमीटर की वृद्धि हुई जो 99 प्रतिशत की वृद्धि है। केंद्र 8,000 करोड़ रुपये की लागत से बाहरी रिंग रोड के बाहर 340 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण करेगा। 2014-15 से ग्रामीण तेलंगाना में 2,700 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण किया गया, इसने तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को गति दी है। मुद्रा ऋणों ने हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाया है।

तेलंगाना राज्य के गठन के बाद रेलवे के लिए केंद्र के आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। रेलवे ने तेलंगाना में 31,281 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लिया। तेलंगाना में 2014-21 के दौरान नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं के 321 किलोमीटर खंड औसतन 45.86 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से चालू किए गए हैं। यह 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग से 164 प्रतिशत अधिक है, जहां प्रति वर्ष 17.4 किमी कमीशन किया गया था।

कोविड-19 अवधि के दौरान केंद्र ने तेलंगाना में 1.92 करोड़ गरीब लोगों को स्वतंत्र रूप से खाद्यान्न वितरित किया। लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से तेलंगाना के निवासियों को मुफ्त वितरण के लिए लगभग 25 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को 433.34 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2014 से अब तक 31.43 लाख से अधिक घरों में अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। 2014 तक तेलंगाना में मात्र 27.45 प्रतिशत शौचालय उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान में तेलंगाना एक खुले में शौच मुक्त राज्य है जिसमें 100 प्रतिशत शौचालय हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 11.11 लाख महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान तेलंगाना में बीसी, एससी और एसटी के विकास के लिए 1,613.64 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

भाजपा — विकसित, समावेशी तेलंगाना के लिए सही और एकमात्र विकल्प

तेलंगाना में भाजपा का तेजी से विकास हो रहा है। अप्रैल 2019 के संसदीय चुनावों में भाजपा ने चार सीटें जीतीं, टीआरएस ने 9 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 3 सीटें जीतीं और एमआईएम ने अपनी सीट बरकरार रखी। भाजपा को 19.45 प्रतिशत वोट मिले, जो 2018 में मिले वोटों से काफी अधिक हैं। इसमें दो राय नहीं कि श्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में राष्ट्रव्यापी लहर सर्वोत्कृष्ट कारक थी।

अक्टूबर/नवंबर, 2020 में हुए दुब्बाका विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री के बेटे और उनके भतीजे के निर्वाचन क्षेत्रों के बीच बसे एक क्षेत्र में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की।

इसके तुरंत बाद दिसंबर, 2020 में हुए ग्रेटर हैदराबाद के लिए नगर निगम चुनावों में भाजपा ने 150 सीटों वाले निगम में 48 सीटों के साथ राजनीतिज्ञों को चौंका दिया। इससे पहले बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थीं। वोटों के मामले में इसने लगभग टीआरएस के बराबर प्रदर्शन किया है। जीएचएमसी के प्रदर्शन के बाद भाजपा टीआरएस के एकमात्र विकल्प के रूप में उभरी, जिसने सभी अटकलों को दूर कर दिया कि टीआरएस का विकल्प कौन बनेगा? कांग्रेस या बी.जे.पी.।

इतना ही नहीं 2021 में हुजुराबाद उपचुनाव ने राज्य में टीआरएस के भाग्य को पलट कर रख दिया। इस चुनाव में सत्ताधारी दल ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया और एक अप्रिय राशि खर्च की। इसके बावजूद भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की। आज हुजूराबाद की जीत ने टीआरएस को एक सबक सिखा दिया जो चुनाव जीतने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर रही है। आज तेलंगाना की जनता चुनावी राजनीति में प्रवेश करने और लोगों की सेवा करने के इच्छुक वास्तविक उम्मीदवारों को प्रोत्साहित कर रही है।

> भाजपा एक ऐसा व्यवहार्य विकल्प रखने का प्रयास करेगी जो लोगों के सामने शहीदों की आकांक्षाओं को सही मायने में साकार करे और अंततः उन्हें इस वंशवादी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करे

स्वाभाविक तौर पर भाजपा के विकास ने मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू ला दिए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक की आलोचना शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई प्रजासंग्राम यात्रा की सफलता के दो चरण पूरे हो चुके हैं और इस यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। इसने मुख्यमंत्री को और परेशान कर दिया है जिससे वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वास्तव में कई अवसरों पर मुख्यमंत्री की भाषा सस्ती, अभद्र और आपत्तिजनक होती है, जो एक मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय है।

मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों की हताशा इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भाजपा राज्य में मजबूत हो रही है। यह स्पष्ट है कि केवल एक दोहरे इंजन वाली सरकार, जिसका दृढ़ विश्वास केवल राष्ट्र और राष्ट्र है, तेलंगाना के लोगों के उत्साही संघर्ष को अर्थ देने में सक्षम होगी।

इन परिस्थितियों में केवल भाजपा, अपने देश-प्रथम दृढ़ विश्वास और ध्यान के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त और घोटाला मुक्त शासन के त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझ सकती है। भाजपा एक ऐसा व्यवहार्य विकल्प रखने का प्रयास करेगी जो लोगों के सामने शहीदों की आकांक्षाओं को सही मायने में साकार करे और अंततः उन्हें इस वंशवादी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करे। ■

मेरे मित्र शिंजो आबे...

नरेन्द्र मोदी

शिंजो आबे न सिर्फ जापान की एक महान विभूति थे, बल्कि विशाल व्यक्तित्व के धनी एक वैश्विक राजनेता थे। भारत-जापान की मित्रता के वे बहुत बड़े हिमायती थे। बहुत दुःखद है कि अब वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके असमय चले जाने से जहां जापान के साथ पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा विजनरी लीडर खो दिया है, तो वहीं मैंने अपना एक प्रिय दोस्त।

आज उनके साथ बिताया हर पल मुझे याद आ रहा है। चाहे वो क्योटो में 'तोज़ी टेंपल' की यात्रा हो, शिंकासेन में साथ-साथ सफर का आनंद हो, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाना हो, काशी में गंगा आरती का आध्यात्मिक अवसर हो या फिर टोक्यो की 'टी सेरेमनी', यादगार पलों की ये लिस्ट बहुत लंबी है।

मैं उस क्षण को कभी भूल नहीं सकता, जब मुझे माउंट फूजी की तलहटी में बसे बेहद ही खूबसूरत यामानाशी प्रीफेक्चर में उनके घर जाने का मौका मिला था। मैं इस सम्मान को सदा अपने हृदय में संजोकर रखूंगा।

शिंजो आबे और मेरे बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं था। 2007 और 2012 के बीच और फिर 2020 के बाद, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हमेशा की तरह उतना ही मजबूत बना रहा।

आबे सान से मिलना हमेशा ही मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ही उत्साहित करने वाला होता था। उनके पास हमेशा नए आइडियाज का भंडार होता था। इसका दायरा गवर्नेंस और इकॉनॉमी से लेकर कल्चर और विदेश नीति तक बहुत ही व्यापक था। वे इन सभी मुद्दों की गहरी समझ रखते थे।

उनकी बातों ने मुझे गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर नई सोच के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उनके सतत सहयोग से गुजरात और जापान के बीच वाइब्रेंट पार्टनरशिप के निर्माण को बड़ी ताकत मिली। भारत और जापान के बीच सामरिक साझेदारी को लेकर उनके साथ काम करना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। इसके जरिए इस दिशा में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला।

पहले जहां दोनों देशों के आपसी रिश्ते केवल आर्थिक संबंध तक सीमित थे, वहीं आबे सान इसे व्यापक विस्तार देने के लिए आगे बढ़े। इससे दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर न केवल तालमेल बढ़ा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को भी नया बल मिला।

वे मानते थे कि भारत और जापान के आपसी रिश्तों की मजबूती, न सिर्फ दोनों देशों के लोगों, बल्कि पूरी दुनिया के हित में है। वे भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए दृढ़ थे, जबकि उनके देश के लिए ये काफी मुश्किल काम था। भारत में हाई स्पीड रेल के लिए हुए समझौते को बेहद उदार रखने में भी उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। 'न्यू इंडिया' तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जापान कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर भारत के साथ खड़ा रहेगा। भारत की आजादी के बाद इस सबसे महत्वपूर्ण कालखंड में उनका यह योगदान बेहद अहम है।

भारत-जापान संबंधों को मजबूती देने में उन्होंने ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसके लिए वर्ष 2021 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

आबे सान को दुनियाभर की उथल-पुथल और तेजी से हो रहे बदलावों की गहरी समझ थी। उनमें दूरदर्शिता भरी थी और यही वजह थी कि वे वैश्विक घटनाक्रमों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर होने वाला प्रभाव पहले ही भांप लेते थे। ये समझ कि किन विकल्पों को चुनना है, किस तरह के स्पष्ट और साहसिक फैसले लेने हैं, समझौतों की बात हो या फिर अपने लोगों और दुनिया को साथ लेकर चलने की बात, उनकी बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल था। उनकी दूरगामी नीतियों – आबेनॉमिक्स – ने जापानी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया और अपने देश के लोगों में इनोवेशन और आंत्रप्रन्योरशिप की भावना को नई ऊर्जा दी।

उन्होंने जो मजबूत विरासत हम लोगों के लिए छोड़ी है, उसके लिए पूरी दुनिया हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। उन्होंने पूरे विश्व में बदलती परिस्थितियों को न केवल सही समय पर पहचाना, बल्कि अपने नेतृत्व में उसके अनुरूप समाधान भी दिया।

भारतीय संसद में वर्ष 2007 के अपने संबोधन में उन्होंने इंडो-पेसिफिक क्षेत्र के उदय की नींव रखी, साथ ही ये विजन प्रस्तुत किया कि किस प्रकार ये क्षेत्र इस सदी में राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को एक नया आकार देने वाला है।

इसके साथ ही वे इसकी रूपरेखा तैयार करने में भी आगे रहे। उन्होंने इसमें स्थायित्व और सुरक्षा के साथ शांत और समृद्ध भविष्य का एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें वे अटूट विश्वास रखते थे। ये उन मूल्यों पर आधारित था, जिसमें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे

जापान के सबसे लंबे समय तक रहनेवाले प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे 8 जुलाई, 2022 को नहीं रहे। उन्हें गोली मार दी गई, जिसके कारण उनका निधन हो गया। 67 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे को एक पूर्व सैनिक ने घर में बनी बंदूक से दो बार गोली मारी। जापान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की हत्या उस समय हुई, जब वह उच्च सदन के चुनाव के लिए चुनाव-प्रचार कर रहे थे।

श्री आबे 2006 में 52 साल की उम्र में जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका पहला कार्यकाल एक साल बाद अचानक समाप्त हो गया। श्री आबे जब 2012 में फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, राजकोषीय प्रोत्साहन, मौद्रिक सुगमता और ढांचागत सुधारों पर जोर दिया। श्री आबे छह बार राष्ट्रीय चुनाव जीते।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से गहरा दुःख हुआ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्हें हमेशा एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने जापान की अथक सेवा की और भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम किया।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

श्री आबे के निधन पर भारत सरकार ने 9 जुलाई को पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया।

श्री आबे के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस ने एक संयुक्त बयान जारी कर क्वाड की स्थापना तथा एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए श्री आबे की महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री शिंजो आबे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री आबे के निधन से जापान और पूरी दुनिया ने एक महान दूरदर्शी राजनेता को खो दिया है और मैंने अपने एक अत्यंत प्रिय मित्र को खो दिया है। मेरे मित्र आबे सान को श्रद्धांजलि...। ■

सर्वोपरि थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों-नियमों और बराबरी के स्तर पर शांतिपूर्ण वैश्विक संबंधों पर भी जोर था। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर हर किसी के लिए समृद्धि के द्वार खोलने का अवसर था।

चाहे Quad हो या ASEAN के नेतृत्व वाला मंच, इंडो पेसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव हो या फिर एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर या Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, उनके योगदान से इन सभी संगठनों को लाभ पहुंचा है। इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में उन्होंने घरेलू चुनौतियों और दुनियाभर के संदेहों को पीछे छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से डिफेंस, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी समेत जापान के सामरिक जुड़ाव में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। उनके इसी प्रयास के कारण यह पूरा क्षेत्र आज बहुत आशान्वित है और पूरा विश्व अपने भविष्य को लेकर कहीं अधिक आश्वस्त है।

मुझे इसी वर्ष मई में जापान यात्रा के दौरान आबे सान से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने उसी समय जापान-इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। उस समय भी वे अपने कार्यों को लेकर पहले की तरह ही उत्साहित थे, उनका करिश्माई व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करने वाला था। उनकी हाजिरजवाबी देखते ही बनती थी। उनके पास भारत-जापान मैत्री को और मजबूत बनाने को लेकर कई नए आइडियाज थे। उस दिन जब मैं उनसे मिलकर निकला, तब यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हमारी यह आखिरी मुलाकात होगी।

वह हमेशा अपनी आत्मीयता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व की गंभीरता, अपनी सादगी, अपनी मित्रता, अपने सुझावों, अपने मार्गदर्शन के लिए बहुत याद आएंगे।

उनका जाना हम भारतीयों के लिए भी ठीक उसी प्रकार दुःखी करने वाला है, मानो घर का कोई अपना चला गया हो। भारतीयों के प्रति उनकी जो प्रगाढ़ भावना थी, ऐसे में भारतवासियों का दुःखी होना बहुत स्वभाविक है। वे अपने आखिरी समय तक अपने प्रिय मिशन में लगे रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। आज वे भले ही हमारे बीच में न हों, लेकिन उनकी विरासत हमें हमेशा उनकी याद दिलाएगी।

मैं भारत के लोगों की तरफ से और अपनी ओर से जापान के लोगों को, विशेषकर श्रीमती अकी आबे और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

ओम शांति! ■

तेलंगाना का भाजपा में विश्वास बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सपन्न होने के बाद 3 जुलाई, 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में एक विशाल 'विजय संकल्प सभा' का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सभा को संबोधित किया।

सभा में उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "तेलंगाना का सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।"

श्री मोदी ने डबल इंजन सरकार के फायदों का जिक्र करते हुए कहा, "2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा के लिए जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना के लोग लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि वे तेलंगाना में भाजपा की सरकार चाहते हैं। इसकी एक और झलक हमने ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में देखी, जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। अन्य राज्यों में भी, हमने देखा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने लोगों का उसमें विश्वास बढ़ाया है। तेलंगाना में भी लोग भाजपा की डबल इंजन सरकार का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।"

किसानों के कल्याण के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "रामगुंडम उर्वरक कारखाना भी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को सशक्त बना रहा है। आप सभी जानते हैं कि यह देश के उन उर्वरक कारखानों में से एक था जो पिछले दशकों में बंद हो गए थे। 2015 में हमने इसे फिर से चालू करने का काम शुरू किया था, अब यहां खाद का उत्पादन शुरू हो गया है। बहुत जल्द यह भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।"

"हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों के जीवन में सुगमता आए, उन्हें उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिले। तेलंगाना में केंद्र सरकार पानी से जुड़ी 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की 5 बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है। पिछले आठ साल में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के धान किसानों से करीब एक लाख करोड़ रुपये का धान खरीदा है।"

केंद्र सरकार द्वारा देश में सफलतापूर्वक किए गए महत्वपूर्ण बदलाव का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "हर क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा बहुत आवश्यक है, चाहे वह कृषि हो या उद्योग हों। गांव हो या तेलंगाना का शहर इलाका, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। हैदराबाद में यातायात को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,500 करोड़ रुपये की लागत से 4 और 6 लेन के कई फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है।"

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो तेलंगाना के हर शहर, हर गांव के विकास के लिए तेजी से काम होगा। हमें सभी को सकारात्मकता से जोड़ना है, हमें सभी को विकास से जोड़ना है।"

तेलंगाना में भाजपा सरकार स्थापित करने का समय : जगत प्रकाश नड्डा

'विजय संकल्प सभा' में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग टीआरएस सरकार के भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान हैं।

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए टीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कलेश्वरम परियोजना केसीआर के लिए जनता का पैसा निकालने के लिए एक एटीएम में बदल गई थी, क्योंकि परियोजना की लागत 32,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने केसीआर पर तेलंगाना की जनता को अब तक 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर की कार (टीआरएस का चुनाव चिन्ह) उनके बेटे, बेटी और दो भतीजों से भरी हुई थी और दूसरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी।

उन्होंने तेलंगाना के लोगों से टीआरएस सरकार के वंशवादी और भ्रष्ट शासन को समाप्त करने और भाजपा की समाज के सभी वर्गों के लिए जारी कल्याणकारी और विकासात्मक नीतियों को लागू करने का मौका देने का आग्रह किया। ■

गुजरात दंगा: सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका, प्रधानमंत्री मोदी को क्लीनचिट

जिन लोगों ने आरोप लगाए, वे मोदीजी से माफी मांगें : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से एएनआई (ANI) ने 25 जून, 2022 को बातचीत की। हम यहां इस बातचीत के मुख्य बिंदु प्रकाशित कर रहे हैं:

- गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी और तथाकथित समाज सेवा के नाम का चोला ओढ़े तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना सच्चाई की जीत है, संविधान में हमारी आस्था की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सिद्ध किया है कि ये सभी आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटिड थे।
- हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18-19 साल की लड़ाई में एक शब्द बोले बगैर सभी दु:खों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर हर वेदना को सहन कर लड़ते रहे। जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर विजयी होकर आता है तो उसकी चमक सोने से भी ज्यादा होती है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र में संविधान के सम्मान का एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दंगे का जो दाग जबरन लगाया गया था, वह भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से धुला है।
- एसआईटी के गठन का ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग की थी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार से इस पर कंसेंट के लिए पूछा था। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं है तो एसआईटी पर हमें क्या आपत्ति है। हमारी सरकार के कंसेंट पर एसआईटी का गठन किया गया था।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में सही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर झूठा आरोप लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अब माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों को कोरे झूठे के तौर पर उजागर किया जा चुका है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसके फैसले के लिए धन्यवाद।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

- एसआईटी के अफसरों का चयन भी हमने नहीं किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। इसमें शामिल अफसर भी भाजपाशासित राज्यों से नहीं लिए गए थे, केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए थे। उस समय तक केंद्र में यूपीए की सरकार आ चुकी थी। पूरी जांच कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान हुई।

- एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से घंटों पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने भी धरना-प्रदर्शन नहीं किया। हम मानते थे कि हमें न्याय प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। जिन-जिन लोगों ने भी मोदीजी पर झूठे आरोप लगाए थे, यदि उनकी अंतरात्मा जागृत है तो आज उन्हें श्री नरेन्द्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से क्षमा मांगना चाहिए।
- भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ ख़ास एजेंडा लेकर राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन झूठे आरोपों को इतना प्रचारित किया। इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि धीरे-धीरे झूठ को ही सब सच मानने लगे।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह साफ़ है कि एक पुलिस अफसर, एक एनजीओ और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने मिलकर सनसनी फैलाने के लिए झूठी बातों को फैलाया और झूठे सबूत गढ़े। जब ये एसआईटी को जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि झूठा जवाब है जिसे एसआईटी ने भी बाद में न्यायालय के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे।
- देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया कि गुजरात सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बार-बार शांति की अपील की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए, वो सुनियोजित नहीं थे, स्वतः स्फूर्त थे। निहित स्वार्थ के तहत एक मैगजीन द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया, क्योंकि जब इस स्टिंग का पूरा फुटेज सामने आया, तब मालूम पड़ा कि स्टिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
- जिस प्रकार से मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उसकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से धज्जियां उड़ा दी है। मैं मानता हूं कि यह जजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है। ■

कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को दी मंजूरी

कुल 2,516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 63,000 कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इस कदम से लगभग 13 करोड़ किसानों, जिनमें से अधिकांश छोटे व सीमांत किसान हैं, को लाभ होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने 29 जून को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी।

इस परियोजना में कुल 2,516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 1528 करोड़ रुपये की होगी, के साथ पांच वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती हैं, जहां लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं।

देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है और पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे व सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित कर दिया गया है और उन्हें साझा बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) के तहत ला दिया गया है।

हालांकि, अधिकांश पैक्स को अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है और वे अभी भी हस्तचालित तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके संचालन में अक्षमता और भरोसे की कमी दिखाई देती है। कुछ राज्यों में पैक्स का कहीं-कहीं और आंशिक आधार पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर में कोई समानता नहीं है और वे डीसीसीबी एवं एसटीसीबी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश में सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके रोजमर्रा के कार्य-व्यवहार के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा मंच पर लाने तथा एक सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) के तहत रखने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने तथा किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दी जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के अलावा पैक्स का कम्प्यूटरीकरण विभिन्न सेवाओं एवं उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के केन्द्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ■

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना हुई चालू

एनटीपीसी-रामगुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना पूरी तरह से संचालित। दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से चालू हो गई है। एनटीपीसी ने 1 जुलाई की आधी रात से रामागुंडम, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम तैरती सौर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।

रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया। इससे पहले एनटीपीसी ने कायमकुलम (केरल) में 92 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा और सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) में 25 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।

रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना उन्नत तकनीक के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं से संपन्न है। मेसर्स भेल के माध्यम से ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण) अनुबंध के रूप में 423 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ■

जून, 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह साल-दर-साल 56% बढ़कर 1,44,616 करोड़ रुपये हुआ

जून, 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 के संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। जीएसटी लागू होने के बाद से पांचवी बार जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार हुआ और मार्च, 2022 से लगातार चौथा महीना है

जून, 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 144,616 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें सीजीएसटी 25,306 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,406 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 75,887 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 40,102 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,018 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 1197 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। जून, 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 के 1,67,540 करोड़ रुपये के संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।

केंद्र सरकार ने आईजीएसटी से 29,588 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 24,235 करोड़ रुपये का एसजीएसटी में निपटान किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने इस महीने में केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर 27,000 करोड़ आईजीएसटी का निपटान किया है। जून, 2022 में नियमित निपटान

के बाद केन्द्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 68,394 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 70,141 करोड़ रुपये रहा।

जून, 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में संग्रह किए गए 92,800 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व से 56 प्रतिशत अधिक है। इस मास के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 55 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेन-देन से प्राप्त राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक है।

यह पांचवीं बार है जब जीएसटी की स्थापना के बाद से मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया और मार्च, 2022 के बाद से चौथा महीना है। जून, 2022 में संग्रह न केवल दूसरा सबसे अधिक रहा, बल्कि कम मासिक संग्रह होने की प्रवृत्ति को भी तोड़ दिया है, जैसाकि अतीत में देखा गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपया रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1.10 लाख करोड़ रुपये के औसत मासिक संग्रह के मुकाबले 37% की वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक सुधार के साथ चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। इस महीने में सकल उपकर संग्रह जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक है। ■

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर अब तक का सर्वाधिक 57,586.48 करोड़ रुपये रहा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 जून को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने बड़ी बाधाओं के बावजूद 2021-22 के दौरान 57,586.48 करोड़ रुपये (7.76 बिलियन डॉलर) मूल्य के 13,69,264 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात में रुपये के संदर्भ में 31.71 प्रतिशत, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 30.26 प्रतिशत तथा मात्रा की दृष्टि से 19.12 प्रतिशत का सुधार हुआ। 2020-21 में भारत ने 43,720.98 करोड़ रुपये मूल्य के (5,956.93 मिलियन डॉलर) 11,49,510 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य उत्पाद का निर्यात किया था।

गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण प्रमुख निर्यात बाजारों में उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत 7.76 बिलियन डॉलर मूल्य के 13,69,264 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात किया जो अब तक का सबसे अधिक सफल निर्यात प्रबंधन रहा।

विदेशी बाजारों में अमेरिका, भारतीय समुद्री खाद्य का मूल्य तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से प्रमुख आयातक बना रहा। अमेरिका ने 3371.66 मिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया और डॉलर मूल्य में इसकी हिस्सेदारी 37.56 प्रतिशत रही।

मात्रा की दृष्टि से चीन भारत से समुद्री खाद्य निर्यात का दूसरा सबसे बड़े स्थान के रूप में उभरा, चीन ने 1,175.05 अमेरिकी डॉलर मूल्य का 2,66,989 मीट्रिक टन आयात किया। भारतीय समुद्री खाद्य का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थान यूरोपीय यूनियन रहा। ■

'डॉ. मुकर्जी एक महान राष्ट्रभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा और महान शिक्षाविद् थे'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 6 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के अग्रदूत एवं देश की एकता व अखंडता के लिए सदैव समर्पित रहने वाले कालजयी व्यक्तित्व डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यालय के बगल में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पार्टी के महामंत्री श्री विनोद तावड़े, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संजय मयूख सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि डॉ. मुकर्जी एक महान राष्ट्रभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा और महान शिक्षाविद् थे। वे इतने प्रतिभावान थे कि महज 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर बने। उनकी शिक्षा, उनके प्रखर ज्ञान एवं उनकी विद्वता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वे 1929 में पहली बार बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। 1930 में वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1940-41 में डॉ. मुकर्जी बंगाल के वित्त मंत्री बने। आजादी के समय जब लगभग पूरे बंगाल और पंजाब के पाकिस्तान में जाने की बात हो रही थी, तब डॉ. मुकर्जी ने इस विषय को सबके सामने रखते हुए इसका प्रखर विरोध किया। उनके आंदोलन के कारण ही आज पश्चिम बंगाल और पंजाब प्रांत भारत का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि डॉ. मुकर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम सरकार में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने देश की पहली उद्योग नीति बनाई। उन्होंने ही खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की थी। वे बहुत कम समय तक उद्योग मंत्री रहे, लेकिन इस अल्प समय में ही उन्होंने देश की औद्योगिक नीति को एक नया आयाम दिया। जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि पंडित नेहरू की सरकार अपने पथ से भटक गई गई, तब उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे पंडित नेहरू की तुष्टीकरण और पाश्चात्य के अन्धान्धुन्ध अनुसरण से दुखी, चिंतित और व्यथित थे। इसलिए देश को एक वैकल्पिक विचारधारा देने के उद्देश्य से उन्होंने 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना की।

श्री नड्डा ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जम्मू-कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर उन्होंने सत्याग्रह किया और बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया। बताते चलें कि उन दिनों जम्मू एवं कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना अनिवार्य होता था। जम्मू एवं कश्मीर में प्रवेश करते हुए डॉ. मुकर्जी ने कहा था कि यह देश की धरती है। मैं यहां आने-जाने के लिए परमिट नहीं लूंगा। उन्हें 11 जून, 1953 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून, 1953 को उनका देहावसान हो गया। इस घटना को लेकर डॉ. मुकर्जी की माता जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे अनसुना कर दिया।

उन्होंने कहा कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता डॉ. मुकर्जी से प्रेरणा लेकर "एक देश में दो निशान, दो विधान नहीं चलेगा" के नारे के साथ सालों-साल संघर्षरत रहे। केंद्र में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर जम्मू-कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की कुशल रणनीति के बल पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 धराशायी हुई और सही अर्थों में हमारी मनीषी डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को प्रेरणास्रोत बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि डॉ. मुकर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से लेकर उनकी जयंती 6 जून तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, अस्पतालों में जाकर लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों के घर जाकर उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याएं दूर करते हैं तथा सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से अविरल कार्य करते रहें। ■

जर्मनी में जी–7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जर्मनी में जी–7 शिखर सम्मेलन से इतर जर्मनी के चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज़ से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अबू धाबी हवाईअड्डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

भीमावरम (आंध्र प्रदेश) में महान स्वतंत्रतासेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh @KamalSandesh

kamal.sandesh KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

आवरण: अजय कुमार सिंह